सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" कुछ लोग अपने हुनर से दंग करते हैं,
और कुछ अपनी असलियत दिखाकर...!!
अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-239 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 17 सितंबर 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न? जेपी नड्डा के बयान के बाद तेज हुई चर्चा

विशेष संवाददाता संदीप सिंह / नईदिल्ली

देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन (17 सितंबर) पर चल रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के बीच बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया कि क्या अभियान के समापन पर पीएम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा जाएगा?

जवाब में नड्डा ने कहा, "पार्टी हर एक तरीके से समय पर निर्णय करती है। अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपका

क्या पद पर रहते हुए मिल सकता है भारत रत्न?

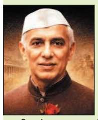

इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं :

- पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न मिला था।

इंदिरा गांधी को 26 जनवरी 1972 को प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश युद्ध के बाद यह सम्मान मिला था।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि जनता महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल कर रही है, ऐसे में इस चर्चा का औचित्य नहीं है। वहीं यह भी याद दिलाया जा रहा है कि पीएम मोदी अतीत में पद पर रहते हुए भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाते रहे हैं।

सुझाव है, अच्छा सुझाव है।" उन्होंने पीएम मोदी को "दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक नेता" भी बताया, जिसके बाद कयास तेज हो गए।

भारत रत्न से जुड़े तथ्य

- शुरूआत 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
- एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है।
- अब तक 53 हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं।

फिलहाल सरकार या राष्ट्रपति भवन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है, चर्चा नड्डा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में है।

जन्मदिन पर विशेष लेख

'कार्यकर्ता से राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता तक नरेंद्र मोदी मैजिक निरंतर बरकरार है'

डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

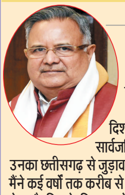

17 सितंबर करोड़ों देशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह उस व्यक्तित्व का जन्मदिवस है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रसेवा के संकल्प को लेकर जिया और आज प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन जितना व्यापक है, उतना ही आत्मीय उनका छत्तीसगढ़ से जुड़ाव भी रहा है। छत्तीसगढ़ की धरती और लोगों से उनकी आत्मीयता को मैंने कई वर्षों तक करीब से देखा और महसूस किया है। मैंने उनके भीतर एक ऐसे कार्यकर्ता को देखा है, जिसके लिए पद से अधिक महत्वपूर्ण संगठन है, राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और व्यक्तिगत सफलता से कहीं बड़ा लक्ष्य लोक सेवा है।

आज पीएम के 76वें जन्मदिवस पर मोदी जी व छत्तीसगढ़ से जुड़े संस्मरण स्मृति में आ रहे हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है, जब 2003 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और मेरे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे थे। उनकी गरिमा के अनुरूप मंच पर व्यवस्थाएं थीं लेकिन मोदी जी ने आसन के सम्मान को छोड़कर न केवल व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली बल्कि कार्यकताओं के साथ जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह जुड़ाव यहीं तक सीमित नहीं रहा, वर्ष 2007 में जब हमारी सरकार ने 3 रुपए किलो (बाद में 1 रुपए किलो) चावल योजना का शुभारंभ किया, तब उन्होंने बड़े विश्वास से कहा था "डॉक्टर साहब, यह योजना छत्तीसगढ़ को बदल कर रख देगी।"

सभी को यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद उन्होंने अब तक 13 बार दिल्ली के लाल किले से संबोधन किया है, लेकिन हम छत्तीसगढ़वासियों की कहानी थोड़ी अलग है। हमने पीएम को 14 बार लाल किले से सुना है क्योंकि 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान अंबिकापुर में उनका एक कार्यक्रम निश्चित था तब हमें यह विश्वास था कि वह जल्द ही दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले हैं, इसलिए हमने पहले ही अंबिकापुर में लाल किले का एक प्रारूप बनवाया था और वहां से उन्होंने भाषण दिया। पीएम के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो मुझे सदैव प्रभावित करता रहा है। वह है बच्चों और विशेषकर दिव्यांग बच्चों के प्रति उनकी सहजता, वर्ष 2015 में दंतेवाड़ा में जावांगा एजुकेशन सिटी में मोदी जी का आगमन हुआ, बतौर मुख्यमंत्री में उनके साथ गया और इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मैं उस दृश्य का साक्षी हूं जब प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के बीच ऐसे घुल-मिल गए कि कब डेढ़ घंटे बीत गए पता ही नहीं चला।

वर्ष 2016 में डोंगरगढ़ की एक जनसभा में जब धमतरी की कुंवरबाई ने अपनी बकरियां बेचकर घर में शौचालय बनवाया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ 104 वर्ष की वयोवृद्ध महिला का सम्मान किया, बल्कि उनके चरण भी छुए। मुझे आज भी उनके वे शब्द याद हैं उन्होंने कहा था, "आज मुझे यहां 104 वर्ष की मां कुंवर बाई का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही जांगला, बीजापुर के एक कार्यक्रम में चरण-पादुकाएं वितरण के दौरान ग्रामीण महिलाएं आईं तो सारी सभा उस वक्त आश्चर्यचकित रह गई जब एक आदिवासी महिला को मोदी जी ने अपने हाथों से चरण-पादुका पहनाकर सम्मान किया था।

जिस बस्तर में मोदी जी ने सभाएं कीं, वहां दशकों से एक समस्या ने जड़ें फैला रखी थीं। वह समस्या थी "नक्सलवाद" जिसने बस्तर को मुख्यधारा से दूर रखा था लेकिन जिस समस्या की चर्चा से सब कतराते थे मोदी जी ने उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। आज जब ऐसे विरले व्यक्तित्व और मां भारती के सपूत नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है तब मैं माता बमलेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि भारत के सपूत नरेंद्र मोदी को उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करें और वो सतत मां भारती की सेवा में तत्पर रहें।

---

13 साल बाद झीरम घाटी हत्याकांड में बड़ा फैसला : NIA कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई मृत्युदंड की सजा

अब हाईकोर्ट में अपील की प्रक्रिया पर नजर रहेगी

नई दृष्टिबिंदु / जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में करीब 13 साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बुधवार को सजा पर फैसला सुनाया। 5 सितंबर को अदालत ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के निर्धारण के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई थी। बुधवार को अदालत ने सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

25 मई 2013 को हुआ था हमला

25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों समेत 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे।

फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता खुला

NIA की विशेष अदालत से मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। दोषियों को अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील का कानूनी अधिकार है। ऐसे में अब इस मामले में आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट में होने वाली संभावित अपील पर निर्भर करेगी।

10 दोषियों को मिली मृत्युदंड की सजा

इस मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मांडवी, मड़कामी देवा, कोसा कवासी, आयत मरकाम, बंजामी सेना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी और महादेव नागा शामिल हैं। सभी आरोपी वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद हैं। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी, जिसके बाद शेष 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही। NIA ने वर्ष 2015 में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

छोटे नक्सलियों को फांसी, बड़े षड्यंत्रकारी सरकार की गोद में : दीपक बैज

रायपुर। झीरम घाटी हत्याकांड में NIA कोर्ट के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह आधा-अधूरा न्याय है। बैज ने कहा कि अदालत ने उन्हीं को सजा दी जिनके खिलाफ सबूत रखे गए। NIA की जांच शुरू से दिशाहीन रही। उसने बड़े नक्सलियों से पूछताछ ही नहीं की। वे समर्पण नीति का फायदा उठाकर खुले घूम रहे हैं और सरकार उनकी संरक्षक बन गई है। झोला उठाने वाले, पानी पिलाने वाले, गड्ढा खोदने वाले और रास्ता बताने वाले छोटे नक्सलियों को आरोपी बनाकर फांसी दी गई।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

NIA ने 200 नक्सलियों के शामिल होने और 39 के नामजद होने की बात कही थी, तो सजा सिर्फ 10 को क्यों? परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यों हटाई गई? हमले की साजिश किसने रची? घायल और जीवित बचे पीड़ितों के बयान तक नहीं लिए गए। शहीदों के पर्स, फाइलें, दस्तावेज हफ्तों तक बिखरे पड़े रहे, किसी का मोबाइल जप्त नहीं हुआ। NIA ने छत्तीसगढ़ पुलिस की SIT जांच को क्यों रोका? तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव, DGP, ADG नक्सल और संदिग्ध समर्पित नक्सलियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। बैज ने कहा कि शुरूआत में NIA की FIR में गणपति (मुपल्ला लक्ष्मण राव), रमन्ना सहित बड़े नेता थे। 21 मार्च 2014 को 26 फरार आरोपियों के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ, लेकिन सितंबर 2014 की चार्जशीट से नाम हटा दिए गए। देवा उर्फ सुक्का, बसवराजू, गणेश उइके, रूपेश उर्फ संजीव, सुरेन्द्र उर्फ रामचंद्र रेड्डी, जयदेव उर्फ बड्डा देव, सोनू उर्फ भूपति जैसे नाम फरार सूची में थे, कई ने सरेंडर भी किया।

उन्होंने बताया कि 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा (DKSZC सदस्य और हमले का मास्टरमाइंड), केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ मोल्ला राजिरड्डी, 20 लाख की इनामी निर्मला उर्फ सुमित्रा, 1 करोड़ के इनामी भूपति उर्फ सोनू दादा और केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता (सितंबर 2025 में तेलंगाना में सरेंडर) जैसे बड़े नक्सलियों से NIA ने पूछताछ तक नहीं की। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती झीरम का सच सामने आए। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक न्यायिक जांच आयोग के खिलाफ स्टे लाए थे। कांग्रेस सरकार ने SIT बनाई तो NIA स्टे ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के पक्ष में फैसला दिया, फिर भी ढाई साल में साय सरकार ने जांच शुरू नहीं की।

---

18 शहीदों की प्रतिमाओं के अनावरण के लिए क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को छत्तीसगढ़ आने का दिया न्योता

नई दृष्टिबिंदु / अर्जुंदा-बालोद

बालोद जिले के ग्राम देवगहन में स्थापित 18 शहीद जवानों की प्रतिमाओं के अनावरण के लिए किसान एवं पूर्व सरपंच लोकेंद्र साहू ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया।

लोकेंद्र साहू ने 14 सितंबर को सूर्यकुमार यादव के जन्मदिन पर मुंबई स्थित उनके चेंबूर निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीमेंट से बनी करीब 4 क्विंटल वजनी आदमकद प्रतिमा भी भेंट की, जिसे मालवाहक वाहन से बालोद से मुंबई ले जाया गया था। मूर्ति का निर्माण बालोद के मूर्तिकार नरेंद्र देवांगन और अमरकंटक के जयपाल ठाकुर ने किया है।

लोकेंद्र साहू ने बताया कि दो वर्ष पहले उन्होंने स्वयं के करीब 10 लाख रुपये खर्च कर सड़क किनारे खेत में 18 शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई हैं। इनमें कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों और गलवान घाटी में शहीद सेना व पुलिस जवानों की प्रतिमाएं शामिल हैं। उद्देश्य युवा पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम जगाना है। श्री साहू चाहते हैं कि अनावरण किसी भारतीय क्रिकेटर के हाथों हो। इसके लिए वे शहीद परिवारों के साथ पहले भी मुंबई दौरे कर चुके हैं। जून 2024 में सचिन तेंदुलकर से मिलने का प्रयास भी किया था।

लोकेंद्र स्वयं 25 साल पहले क्रिकेटर बनने का सपना लेकर मुंबई कोचिंग लेने गए थे और आज युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। मुलाकात में सूर्यकुमार यादव ने प्रतिमा देखकर खुशी जताई और जल्द छत्तीसगढ़ आकर शहीद प्रतिमाओं और परिवारों से मिलने का आश्वासन दिया।

नशे में युवक चढ़ा बिजली के खंभे पर, चला हाईवोल्टेज ड्रामा

धमतरी। जिले में शराब के नशे में एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक ऊपर बैठकर हंगामा करता रहा। घटना के दौरान नीचे मौजूद लोग सांस रोककर पूरा घटनाक्रम देखते रहे। गनीमत रही कि युवक करंट की चपेट में नहीं आया और पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शांति कॉलोनी चौक का है। जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय एक युवक शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शांति कॉलोनी चौक पहुंचा। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि युवक अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में युवक काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

यूपीआई पर 0.4% MDR का विवाद : व्यापारियों पर बोझ और विदेशी कंपनियों को फायदे के आरोप

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए एमडीआर (Merchant Discount Rate) फ्रेमवर्क ने सियासी और आर्थिक बहस तेज कर दी है। नए प्रस्ताव के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% तक चार्ज लग सकता है, जिस पर अधिकतम 300 रुपये की कैपिंग होगी।

सरकार का दावा है कि यह चार्ज आम आदमी के P2P ट्रांसफर पर नहीं, बल्कि मर्चेंट पर लगेगा। नियमों के अनुसार जिन व्यापारियों के खाते में 3 महीने में औसतन हर महीने 1 लाख रुपये से अधिक यूपीआई प्राप्ति होती है, वे इसके दायरे में आएंगे। आलोचकों का कहना है कि रोज 3,000 रुपये का कारोबार करने वाला छोटा दुकानदार भी

इसकी जद में आ जाएगा।

फैसले के बाद फिनटेक कंपनियों पेटीएम, मोबिक्विक जैसी कंपनियों के शेयरों में 2 से 8% की तेजी देखी गई। सिटी बैंक के अनुमान के मुताबिक इससे पेमेंट कंपनियों को 16,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है। चर्चा यह भी है कि यूपीआई मार्केट का करीब 86% हिस्सा Google Pay और PhonePe (वॉलमार्ट समर्थित) के पास है, ऐसे में सबसे बड़ा लाभ विदेशी कंपनियों को होगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सरेंडर किया है। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी पुनर्विचार की मांग की है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स ने चेतावनी दी है कि छूट नहीं मिली तो फ्यूल रिटेलर 2,000 से ऊपर का यूपीआई लेना बंद कर सकते हैं।

सरकार और NPCI का कहना है कि व्यापारी MRP से ज्यादा नहीं वसूल सकते, लेकिन व्यापारियों का तर्क है कि अतिरिक्त लागत अंततः दाम बढ़ाकर या नकद मांग कर ग्राहक पर ही डाली जाएगी।

विजय शर्मा ने एम्स रायपुर में महाराष्ट्र सड़क हादसे के घायलों से की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नागपुर-रायपुर राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र के लोगों से उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने एम्स रायपुर पहुंचकर मुलाकात की। रायपुर एम्स पहुंचे श्री शर्मा ने घायलों और उनके परिजनों से आत्मीयता से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। श्री शर्मा ने एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी मुलाकात कर घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, चल रहे उपचार और आगे की चिकित्सा प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की तथा सभी घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

संवत्सरी : इतिहास, प्रेरणा और आत्मानुभूति का महान पर्व : डॉ. मणिभद्र मुनि महाराज

तपस्वियों की साधना की धर्मसभा में उपस्थित, श्रावक-श्राविकाओं ने अनुमोदना करते हुए उनके आत्मबल एवं संयम की सराहना की

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

84 लाख जीव योनियों से क्षमायाचना

संवत्सरी महापर्व के अवसर पर सूर्यास्त के पश्चात जैन विधि-विधान के अनुसार संवत्सरिक प्रतिक्रमण की आराधना की गई। साधक एवं श्रावक-श्राविकाओं ने वर्षभर में जाने-अनजाने में हुए अपराधों, प्रमादों एवं कषायों के लिए आत्मावलोकन करते हुए क्षमायाचना की। इस अवसर पर 84 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना करते हुए जैन शास्त्रों का पाठ एवं प्रतिक्रमण किया गया। वातावरण में आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और क्षमाभाव की अनुभूति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। संवत्सरी महापर्व ने सभी को यह प्रेरणा दी कि जीवन में केवल बाहरी उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, संयम, तप, त्याग, क्षमा और मैत्री का भाव भी जागृत होना चाहिए। यही संवत्सरी का वास्तविक संदेश और आत्मानुभूति का मार्ग है।

आध्यात्मिक वातावरण में चल रहे पर्युषण पर्व का आज अंतिम दिवस संवत्सरी महापर्व के रूप में श्रद्धा, साधना, तपस्या, त्याग और आत्मचिंतन के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में जय आनंद मधुकर रतन भवन, बांधा तालाब, दुर्ग में भी पर्युषण पर्व के दौरान धर्म-ध्यान, त्याग, तपस्या एवं जप-अनुष्ठान की आराधना निरंतर चलती रही।

धर्मसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र संत डॉ. मणिभद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि मानव स्वभाव से आनंद-पिपासु और उत्सवप्रिय है, लेकिन गृहस्थ जीवन की अनेक चिंताएं उसे चारों ओर से घेरे रहती हैं। जब मनुष्य इन चिंताओं से मुक्त होकर आनंद में निमग्न होता है, तब जीवन में एक नई बहार आती है और जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसी आनंदमयी तिथियों को ही पर्व कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि हर देश और हर समाज में पर्व आनंद एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। किसी समाज की जीवंतता और उत्साह का आकलन उसके पर्व एवं त्योहारों से किया जा सकता है। भारत का सौभाग्य है कि यह ऋषि एवं कृषि की भूमि होने के साथ-साथ उत्सवों और त्योहारों की भी भूमि है। यहां पर्वों की समृद्ध परंपरा रही है। ह्यसात वार नौ त्योहारह्व की लोकोक्ति भी भारत की इसी उत्सवप्रिय संस्कृति को दशार्ती है।

तपस्वियों का हुआ अभिनंदन

संवत्सरी महापर्व के अवसर पर धर्मसभा में तपस्या करने वाले साधकों का अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान पारिवारिक रिश्तों में तपस्या के प्रति श्रद्धा और सम्मान का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मामा-भांजे, देवरानी-जेठानी, पिता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी तथा सास-बहू की जोड़ियों ने एक-दूसरे की तपस्या का अभिनंदन कर साधकों का उत्साहवर्धन किया। मामा-भांजे की जोड़ी में कांतिलाल पारख ने विक्रम, देवरानी-जेठानी की जोड़ी में इंदिरा ने सरल बोहरा, पिता-पुत्र की जोड़ी में राकेश ने प्रतीक संचेती, पति-पत्नी की जोड़ी में विक्रम ने स्वीटी एवं रोशन ने तनुश्री भंडारी, तथा सास-बहू की जोड़ी में इंदिरा ने युक्ति की तपस्या का अभिनंदन किया। इसी क्रम में श्रमण संघ स्वाध्याय मंडल के प्रमुख सदस्य अमन सुराणा ने 15 उपवास की साधना पूर्ण की। वहीं टोनू छाजेड़, विक्रम पारख, सिद्धार्थ चौरड़िया, अंकित रतन बोहरा एवं प्रणब संचेती ने आठ-आठ उपवास की कठिन साधना संपन्न की।

खास खबर

बिजली उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर का बोझ थोपना बंद करे सरकार : अरुण वोरा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं की जेब पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

एक कार्यक्रम के दौरान जब अरुण वोरा आम लोगों के बीच पहुंचे तो कई बिजली उपभोक्ताओं ने उन्हें रास्ते में रोककर स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी परेशानियां बताईं। लोगों ने वोरा से कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बढ़ते बिलों को लेकर वे चिंतित हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिजली की खपत के अनुरूप बिल इतना अधिक क्यों आ रहा है। उपभोक्ताओं ने अपनी समस्या रखते हुए अरुण वोरा से कहा कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाइए और हमारी समस्या का निराकरण कराइए। जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अरुण वोरा ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिजली बिल आम परिवार के मासिक बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं में असंतोष और आशंका है, तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

अरुण वोरा ने कहा कि पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब बिजली के मीटर बदलने के नाम पर नई व्यवस्था में धकेला जा रहा है। सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ क्या मिलेगा और उनकी बिजली खपत एवं बिलिंग व्यवस्था किस तरह प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं के नाम पर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन यदि इन योजनाओं का आर्थिक भार आम जनता की जेब पर पड़ता है तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। बिजली हर परिवार की मूलभूत आवश्यकता है, इसे ऐसी व्यवस्था में नहीं बदला जाना चाहिए जिससे गरीब, मध्यमवर्गीय और छोटे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़े।

वोरा ने कहा कि यदि स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी रहती है या लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होता, तो कांग्रेस सड़क से लेकर जनमंच तक इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा, जनता को सस्ती, निर्बाध और पारदर्शी बिजली चाहिए। सरकार को जनता की आशंकाओं और हितों को दरकिनार कर कोई व्यवस्था थोपने के बजाय पहले उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी और भरोसा देना चाहिए। सरकार से मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया, बिलिंग प्रणाली और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। साथ ही उपभोक्ताओं की आपत्तियों और सुझावों को गंभीरता से सुना जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जनता द्वारा सीधे अपनी समस्या बताना इस बात का संकेत है कि स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं के मन में गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की इस समस्या को कांग्रेस मजबूती से उठाएगी और उपभोक्ताओं के हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े किसी भी फैसले को कांग्रेस चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो उपभोक्ताओं के हित में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

कल आराधना नागवंशी की वार्ता आकाशवाणी से होगी प्रसारित

भिलाई। आराधना नागवंशी की वार्ता सोशल मीडिया और युवा का प्रसारण आकाशवाणी रायपुर के युववाणी कार्यक्रम में 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को शाम 5.10 बजे किया जाएगा। आराधना, एफएसएनएन के राजभाषा अधिकारी छगन लाल नागवंशी की सुपुत्री हैं। आराधना हिंदी में कहानी, कविता तथा समसामयिक विषयों पर आलेख एवं लेख निरंतर लिखती रही हैं। उनकी वार्ता का प्रसारण 981 किलोहर्ट्ज सहित छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों तथा मोबाइल एप पर सुना जा सकेगा।

बिहान से जुड़कर मनीषा ने संवारा अपना भविष्य, पार्लर व्यवसाय को मिला विस्तार

सफलता की कहानी : आत्मनिर्भरता के साथ लखपति दीदी बनने की ओर बढ़ाए कदम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कभी घर के छोटे से कमरे में सीमित संसाधनों के साथ पार्लर चलाने वाली ग्राम पंचायत फुंडा की श्रीमती मनीषा ठाकुर अपनी स्वयं की दुकान संचालित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद उन्हें समूह की ताकत, बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं की जानकारी मिली, जिसका लाभ उठाकर उन्होंने अपने हुनर को व्यवसाय का रूप दिया। आज उनका पार्लर व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया बन गया है और वे लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मनीषा ठाकुर अम्बे स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं। समूह में कुल 14 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिहान से जुड़ने से पहले मनीषा घर से ही पार्लर का संचालन करती थीं। सीमित संसाधनों और छोटी जगह के कारण वे अपने व्यवसाय का अधिक विस्तार नहीं कर पा रही थीं। आमदनी भी नियमित नहीं थी।

समूह से मिली जानकारी, ऋण सुविधा से खुला आगे बढ़ने का रास्ता

बिहान स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद मनीषा को समूह की बैठकों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था, ऋण सुविधा और व्यवसाय विस्तार की जानकारी मिली। उन्होंने उपलब्ध ऋण सुविधा का लाभ लेकर अपने पार्लर व्यवसाय में आवश्यक संसाधन जुटाए और अपनी स्वयं की दुकान शुरू की। दुकान मिलने से ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के साथ व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

सामान्य दिनों में 30 से 35 हजार, सीजन में 1 से 2 लाख तक पहुंचती है आय

मनीषा बताती हैं कि वर्तमान में उनके पार्लर से सामान्य दिनों में लगभग 30 से 35 हजार रुपये प्रतिमाह की आय हो जाती है। वहीं शादी-विवाह

और त्योहारों के सीजन में ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर उनकी आमदनी 1 से 2 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। बढ़ती आय ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि मनीषा के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है।

हुनर को मिला मंच, बढ़ा आत्मविश्वास

मनीषा कहती हैं कि उनके पास पार्लर का काम करने का हुनर पहले से था, लेकिन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों और सही जानकारी की जरूरत थी। बिहान समूह से जुड़ने के बाद उन्हें यह अवसर मिला। समूह के माध्यम से मिली जानकारी और ऋण सुविधा ने उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान किया। आज मनीषा अपने व्यवसाय का संचालन स्वयं कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उनकी सफलता यह बताती है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, अवसर और सहयोग मिले तो वे अपने हुनर को आजीविका का मजबूत साधन बना सकती हैं।

अन्य महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने कहा कि बिहान स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। मनीषा ठाकुर की सफलता इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं अपने हुनर और छोटे व्यवसाय को समूह के सहयोग से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

मनीषा की कहानी गांव की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने हुनर के बावजूद संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पातीं। बिहान से जुड़कर उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किया, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से लखपति दीदी बनने की राह भी तैयार की है।

एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए शिविरों का आयोजन जारी

धान खरीदी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों एवं उनके सह-हिस्सेदारों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टेक पंजीयन होना अनिवार्य है। इस हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समिति में संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से एग्रीस्टेक पंजीयन का कार्य अपने आश्रित ग्रामों में शिविर आयोजित कर किया जा रहा है। शिविरों में जिले के सभी तहसील के कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी भी उपस्थित रहकर शासन की महत्वपूर्ण योजना में सहयोग प्रदाय कर रहे है। इस संबंध में पूर्व ही सहकारिता विभाग, अधिकक्षक भू-अभिलेख एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों के संमिति प्रबंधक / प्रभारियो की समीक्षा बैटक जिले के कलेक्टर द्वारा जा चुकि है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना एग्रीस्टेक पंजीयन धान नही बिकेगा, सह खातेदारों का भी पंजीयन होना भी आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस वर्ष 2026-27 में धान बिकी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं सह-खातेदारों का बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) अनिवार्य रहेगा।

यातायात पुलिस दुर्ग का जागरूकता कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय साइकलिस्ट संतोष मिश्रा ने साझा किया अनुभव

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा शासकीय स्कूल कैंप-01 में साइबर सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, बालिका सुरक्षा और नशा मुक्ति पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय साइकलिस्ट संतोष मिश्रा ने साइकिल से भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की यात्रा कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वे 15 अगस्त 2001 से भद्रक, उड़ीसा से यह अभियान चला रहे हैं और पूर्व में जगदलपुर, बालोद में भी बच्चों को जागरूक कर चुके हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल ने साइबर अपराध से बचाव के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करने, डळढ और बैंक जानकारी साझा न करने तथा ठगी होने पर तुरंत शिकायत करने की सलाह दी। साथ ही नशे से दूर रहने, यातायात नियमों के पालन और बालिका सुरक्षा पर भी जागरूक किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल, प्राचार्य, शिक्षकगण, आम नागरिकों सहित करीब 250 छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

44 दिवसीय महाअनुष्ठान में श्रद्धालु होंगे सहभागी

दुर्ग। जैन धर्म की प्राचीन आध्यात्मिक साधना एवं भक्तिभाव से जुड़ा भक्तामर स्तोत्र संपुट अनुष्ठान लगभग 30 वर्षों के पश्चात श्रमण संघ परिवार में पुन: आयोजित होने जा रहा है। मानव मिलन संस्थापक, नेपाल केसरी राष्ट्र संत डॉ. मणिभद्र मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 सितंबर से 30 अक्टूबर तक 44 दिवसीय यह विशेष महाअनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्रावक-श्राविकाओं सहित जैन समाज में विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का विषय रहा है। इसके 48 पदों की साधना को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्तामर की प्रत्येक गाथा के साथ विशिष्ट आध्यात्मिक भाव और साधना जुड़ी हुई है। श्रद्धालु शुद्ध एवं पवित्र भावों से इसके पाठ, जाप और अनुष्ठान को आत्मशांति, सकारात्मकता तथा आध्यात्मिक लाभ का माध्यम मानते हैं।

30 सितम्बर को संभागीय मुख्यालयों में होगा एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन व रैली

मोदी की गारंटी लागू करने सहित कर्मचारी हित की विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं सम्बद्ध संगठनों द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 30 सितम्बर 2026 को संभागीय मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं रैली आयोजित की जाएगी। आंदोलन के पश्चात कलेक्टर के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

संघ ने बताया कि कर्मचारियों के लिए की गई मोदी की गारंटी को लागू करने की मांग को लेकर पूर्व में तहसील एवं जिला मुख्यालयों में कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन एवं प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश के सभी विधायक एवं सांसद सहित जनप्रतिनिधियों को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, किंतु मांगों पर निर्णय नहीं लिये जाने के कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

संघ की प्रमुख मांगों में केन्द्रीय तिथि से महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करने, डी.ए. एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का प्रावधान करने, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का वेतनमान पुनरीक्षित करने, शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का लाभ देने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के स्थान पर सीमित विभागीय परीक्षा का प्रावधान करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्र पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को

रिक्त पदों पर नियमित करने तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।

सम्बद्ध संगठनों की प्रमुख मांगें

संघ से सम्बद्ध संगठनों ने ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का पदनाम परिवर्तित कर ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी एवं सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पदनाम सेक्टर स्वास्थ्य अधिकारी करने, आईटीआई के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मानजनक वेतन एवं पदोन्नति का लाभ देने तथा विभिन्न पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर प्रदान करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के मूल कर्मचारियों का वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संविलियन, दिव्यांगजन अधिकारी/कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति एवं रिक्त पदों पर भर्ती तथा वर्क डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में पदोन्नति का लाभ देने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। साथ ही पेंशनरों के लिए भी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने की मांग की गई है।

संघ ने प्रदेश के सभी कर्मचारी-अधिकारियों एवं सम्बद्ध संगठनों के पदाधिकारियों से 30 सितम्बर 2026 को अधिक से अधिक संख्या में संभागीय मुख्यालय पहुंचकर धरना, प्रदर्शन एवं रैली को सफल बनाने की अपील की है।

म्यूल बैंक खातों पर दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

खातों से लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का हुआ खुलासा, 6 खाताधारक हुए गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में उपयोग हो रहे म्यूल बैंक खातों पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 679/2026 धारा 318(2), 318(3), 317(4) बीएनएस के तहत थाना सुपेला और ACCU की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

मामला क्या है

आरोपियों ने 2 हजार से 15 हजार रुपये के कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर ठगों को उपलब्ध कराए थे। जांच में इन खातों से लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है।

गिरफ्तार आरोपी में दिनेश सोना (22) इस्लाम नगर, सुपेला, हेमन्त कुमार मिश्रा (37) शंकर पारा, सुपेला, मोहम्मद आरिफ (30) टंकी मरौदा, वीरेन्द्र विश्वकर्मा (34) हाउसिंग बोर्ड चरौदा, अखिलेश गुप्ता (55) अनाज लाइन, सुपेला और रीना देवी, शारदा पारा, छावनी शामिल हैं। पुलिस ने पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम और मोबाइल जब्त किए हैं।

पुलिस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपना बैंक खाता या सिम दूसरों को न दे, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई होगी। साइबर ठगी पर 1930 या http://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

उतई पुलिस की कार्रवाई : 2 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

भिलाई। थाना उतई पुलिस ने उमरपोटी बोगदा पुल के पास घेराबंदी कर गांजा बिक्री करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भूपेन्द्र उर्फ राजू गायकवाड़ (38), निवासी भाठापारा वार्ड-13, परसदा, थाना गुण्डरदेही, बालोद को पकड़ा। उसके पास से 2 किलो 12 ग्राम गांजा (कीमत करीब 1 लाख रुपये), 4,010 रुपये नगद और परिवहन में प्रयुक्त टीवीएस जूपिटर CG 07 CY 0302 जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध क्र. 465/2026 धारा 20(ख)(ii)(इ) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

भिलाई में सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान शुरू

बैकुंठधाम तालाब और सिविक सेंटर में चली सफाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर सेवा संकल्प अभियान और स्वच्छता ही सेवा के तहत शहर में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर 16 सितंबर को सभी जोन में सफाई अभियान चलाया गया। जोन-3 में बैकुंठधाम मंदिर के पास तालाब और आसपास के क्षेत्र की विशेष सफाई की गई, ताकि 17 सितंबर को जनप्रतिनिधि और नागरिक "आशीर्वाद का दीया" जलाकर विकसित भारत का संदेश दे सकें।

जोन-5 में सिविक सेंटर अर्जुन रथ के समीप, जोन-1 में वार्ड-10 लक्ष्मी मार्केट, वार्ड-7 दाऊ बाड़ा तालाब, जोन-2 में वार्ड-22 विश्व बैंक कॉलोनी और जोन-4 में केनाल रोड, नंदनी रोड से जीरो पॉइंट ट्रांसपोर्ट नगर तक मुख्य मार्ग की सफाई की गई।

महाराजा चक्रधर सिंह की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा चक्रधर समारोह : राज्यपाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने संगीत, नृत्य और कला की समृद्ध परंपरा से जुड़ी रायगढ़ की धरती पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह का सोमवार को महाराजा चक्रधर की तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत भव्य शुभारंभ किया। राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल कला प्रस्तुतियों का मंच नहीं, बल्कि महाराजा चक्रधर सिंह की कला-साधना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 14 से 23 सितम्बर तक रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में देश-प्रदेश के ख्यातिप्राप्त कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाएं भी गायन, वादन, नृत्य और लोककला की प्रस्तुतियां देंगी।

राज्यपाल ने कलाकारों का किया सम्मान : शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का सम्मान किया। पद्मश्री डॉ. उषा बारले, पद्मश्री अनुज शर्मा सहित अन्य कलाकारों और कला गुरु स्वर्गीय वेदमणि सिंह ठाकुर के शिष्यों ने प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह की सांस्कृतिक गरिमा को और ऊंचाई प्रदान की। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह की कला साधना और उनकी दूरदृष्टि को स्मरण करने का अवसर है। रायगढ़ भारतीय शास्त्रीय कलाओं की महत्वपूर्ण धरोहर भूमि है और रायगढ़ घराने के कथक ने देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। महाराजा चक्रधर सिंह ने राजसिंहासन से अधिक महत्व कला को दिया। उन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और संगीत, नृत्य एवं साहित्य को आमजन के जीवन से जोड़ने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह की कृतियां नर्तन सर्वस्व, तालतोय निधि और राग रत्न मंजूषा आज भी कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उन्होंने अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि कला किसी एक स्थान या केंद्र की मोहताज नहीं होती। जहां निरंतर साधना होती है, वही स्थान कला का तीर्थ बन जाता है। रायगढ़ की पहचान आज संगीत, घुंघरुओं की झंकार, तबले की थाप और नृत्य की भाव-भंगिमाओं से जुड़ी है।

राज्यपाल ने कहा कि चक्रधर समारोह अब केवल एक शासकीय या संस्थागत आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह रायगढ़ की सांस्कृतिक धड़कन बन चुका है। देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलना इस समारोह की विशेषता है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में अपनी जड़ों के प्रति जुड़ाव पैदा करते हैं। युवाओं को परंपरा के साथ नवाचार को जोड़ते हुए कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पंथी, राउत नाचा, भरथरी, सुआ, करमा सहित आदिवासी नृत्य और लोकगीत हमारी सांस्कृतिक विविधता की पहचान हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है और चक्रधर समारोह इसी सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण जरूरी : राज्यपाल ने कहा कि विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी जरूरी है। रायगढ़ औद्योगिक विकास के साथ-साथ अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। पिछले वर्ष समारोह ने अपने 40 वर्ष पूरे किए और अब 41वां समारोह नई ऊर्जा और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनते हैं और कला को समाज से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति केवल हमारी पहचान नहीं, बल्कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने का माध्यम हैं। आज के डिजिटल युग में भी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़ाव पिछड़ापन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और ताकत है। चक्रधर समारोह अतीत को याद करने के साथ-साथ उस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

खास खबर

बड़ौदा पर छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम ने की जीत हासिल, 7 विकेट से हराया

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉ. के थिम्मापीयाह मेमोरीयल आमंत्रण किकेट टूनार्मेंट में छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम ने बड़ौदा पर शानदार जीत दर्ज की। चार दिवसीय मैच के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ की टीम ने 228 रनों के लक्ष्य को आसानी से पा लिया। छत्तीसगढ़ की ओर से अनुज तिवारी व विकल्प तिवारी ने 70-70 रनों की पारी खेलकर जीत में अहम योगदान दिया।

प्रतियोगिता के तहत छत्तीसगढ़ की सीनीयर टीम का यह तिसरा मैच रहा। 13 से 16 सितंबर के बी सीएमआर युनिवसीर्टी स्टेडियम बेंगलुरू में बड़ौदा के खिलाफ खेला गया। बडौदा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बडौदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुये अपनी पहली पारी में 83 ओवरों में 10 विकेट खोकर 286 रन बनाये। बडौदा की ओर से मितेश पटेल ने 68 रन तथा मनन सोलंकी ने नाबाद 47 रन बनाये। उनके अतिरिक्त अक्षय मोरे ने 34 रनों का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की ओर से संदिप वारीयर तथा वरुण सिंह भुई ने शानदार गेंदबाजी करते हुये 4-4 विकेट प्राप्त किये।

छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में 104.2 ओवरों में 10 विकेट खोकर 348 रन बनाये। छत्तीसगढ़ की ओर से अमनदीप खरे ने 77 रन तथा अनुज तिवारी ने 73 रनों की शानदार पारी खेली। पहले विकेट के लिये अनुज तिवारी (73 रन) तथा संगीत सोनी (57 रन) के मध्य 109 रनों साझेदारी हुयी। राहुल प्रधान ने भी 66 रनों का योगदान दिया। बडौदा की ओर से परिक्षित पाटीदार ने 4 विकेट तथा भार्गव भट्ट ने 4 विकेट प्राप्त किये।

बडौदा ने अपनी दूसरी पारी में 79 ओवरों में 8 विकेट खोकर 290 रन बनाये है। बडौदा की ओर से हर्ष देसाई ने 68 रन तथा मनन सोलंकी ने 64 रन बनाये। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से वरुण सिंह भुई ने शानदार गेंदबाजी करते हुये 6 विकेट प्राप्त किये। 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ ने अपनी दूसरी पारी में 58.1 ओवरों में 3 विकेट खोकर 232 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। छत्तीसगढ़ की ओर से अनुज तिवारी तथा विकल्प तिवारी ने 70-70 रनों का योगदान दिया। उनके अतिरिक्त राहुल प्रधान ने 52 रन बनाये। छत्तीसगढ़ ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया।

बस्तर-सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग नेटवर्क का करें विस्तार : मुख्यमंत्री साय

गांव के नजदीक बैंकिंग सुविधा से वित्तीय समावेशन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-बस्तर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एचडीएफसी बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि पर बैंक प्रबंधन, अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार किए गए विशेष लोगो का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मजबूत और सर्वसुलभ बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले वर्षों में बैंकिंग सेवाओं में तेजी से विस्तार हुआ है और डिजिटल तकनीक ने वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक सहज बनाया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक भी समान रूप से पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग नेटवर्क का और विस्तार करते हुए विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा अंचल के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जनजातीय बहुल है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे और सरकार की

विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक सुगमता से उन तक पहुंच सकेगा। श्री साय ने कहा कि गांव के नजदीक बैंक की शाखा या बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने का प्रभाव केवल बैंकिंग लेन-देन तक सीमित नहीं रहता। इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। ग्रामीणों को अपने खाते से संबंधित सामान्य कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, उनका समय और संसाधन बचता है तथा बचत और औपचारिक बैंकिंग के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता सुशासन की व्यवस्था को भी मजबूत करती है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार का लाभ नागरिकों के साथ-साथ शासन को भी मिलता है, क्योंकि इससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आती है। किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण तथा छोटे व्यवसायियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों और छोटे उद्यमों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बैंकिंग संस्थाएं यदि इन समूहों तक ऋण, वित्तीय साक्षरता और अन्य बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को और मजबूत करें तो महिलाओं की उद्यमशीलता को बड़ा संबल मिल सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने परिवार के साथ पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिसमें युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के भी अधिक से अधिक अवसर मिलें। प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा और आगे बढ़ने की क्षमता है। उनके विचारों और उद्यमशीलता को वित्तीय सहयोग से जोड़ने में बैंक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने से प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास के नए दौर से गुजर रहा है। प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार के साथ उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र और नई अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास के इन अवसरों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं, बल्कि लोगों के सपनों और आर्थिक संभावनाओं को संसाधनों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी हैं। किसी युवा को अपना व्यवसाय प्रारंभ करना हो, किसी महिला समूह को अपने उत्पादों का विस्तार करना हो, किसी किसान को अपनी आय बढ़ाने के लिए नई गतिविधि शुरू करनी हो अथवा किसी छोटे व्यापारी को अपना कारोबार आगे बढ़ाना हो - सुलभ वित्तीय सहायता उनके प्रयासों को नई दिशा दे सकती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वित्तीय साक्षरता पर भी जोर देते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के साथ नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित लेन-देन, बचत, बीमा और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जागरूक करना भी आवश्यक है। विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर लोगों को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की यात्रा में सरकार के साथ निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में निवेश, उद्यमिता, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग संस्थाएं राज्य सरकार की विकासपरक पहलों में महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एचडीएफसी बैंक अपने अनुभव और व्यापक बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में अपनी सहभागिता को आने वाले वर्षों में और विस्तार देगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में एचडीएफसी बैंक की 25 वर्षों की यात्रा को महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि यह अवसर बीते वर्षों की उपलब्धियों के साथ भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बैंक आने वाले समय में शहरों के साथ गांवों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में अपनी पहुंच बढ़ाकर अधिक से अधिक परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ेगा।

इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड अरुण मेदीरत्ता, ब्रांच बैंकिंग हेड सेंट्रल इंडिया प्रतीक शर्मा सहित बैंक के माई प्रतिनिधि उपस्थित थे।

34 करोड़ से अधिक के सड़क विकास कार्यों की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भैयाथान क्षेत्रवासियों को सड़क विकास की बड़ी सौगात देते हुए 34 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों का कार्यप्रारम्भ पूजन किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी तथा क्षेत्र में विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा हैं। मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना पहुंचे और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं का लाभ किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों सहित आम नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत और टिकाऊ अधोसंरचना ही विकास कार्यों का स्थायी लाभ लोगों तक पहुंचा सकती है।

18 किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण : कार्यप्रारम्भ पूजन किए गए प्रमुख कार्यों में डुमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से केंवरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन शामिल है। लगभग 30.41 करोड़ रुपये की लागत से 18 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत बिटुमिनस कंक्रीट एवं शोल्डर कार्य के साथ 6,570 मीटर नाली, 300 मीटर टो-वॉल, 140 मीटर रिटेनिंग वॉल, 8 एचपीसी तथा 7 स्लैब पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सड़क के उन्नयन से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आवागमन सुविधा बेहतर होगी।

दरीपारा-दनौली मार्ग से झम्मनपारा को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी : इसी क्रम में झम्मनपारा में दरीपारा से दनौली तक 3.20 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भी कार्यप्रारम्भ पूजन किया गया। इस कार्य के लिए 374.76 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना में 3.20 किलोमीटर सड़क, 0.90 किलोमीटर सीसी रोड, 1,200 मीटर नाली, 90 मीटर रिटेनिंग वॉल तथा 6 एचपीसी पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

सरिया क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति की मंत्री चौधरी ने की समीक्षा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।

बैठक में विकास परियोजनाओं की प्रगति, कार्यों के क्रियान्वयन तथा निर्धारित समय-सीमा में उन्हें पूर्ण करने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की सतत निगरानी करने तथा कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने देने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की बात कही।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रत्येक कार्य का लाभ आम नागरिकों तक समय पर पहुंचे, यह शासन की प्राथमिकता है। विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग से कार्यों में गति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का भव्य शुभारंभ

राज्यपाल रमेन डेका ने किया 'Chhattisgarh Local Body Electionf Year Book–2026' का विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शुभारंभ समारोह के विशेष अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने 'Chhattisgarh Local Body Electionf Year Book–2026' के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय

पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार तथा आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने सम्मेलन में देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों और स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े समसामयिक विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों तथा निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह एवं आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन के प्रथम दिन डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, पारदर्शिता तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की शुरूआत हुई। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री विजय देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्थायी समिति के संयोजक श्री सुधांशु पांडे ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दो दिवसीय यह सम्मेलन देश में स्थानीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, निर्वाचन व्यवस्थाओं में आधुनिक तकनीक के समावेश तथा विभिन्न राज्यों के अनुभवों और नवाचारों को साझा करने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कल 17सितम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक होनी है। इसके बाद, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी केपिटल सिटी, नया रायपुर के निर्माण और विकास के बारे में प्रस्तुतीकरण होगा। तत्पश्चात सभी अतिथियों को नया रायपुर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भ्रमण भी शामिल है।

संपादकीय

सुधार करके ही रोका जा सकता है भ्रष्टाचार को

शासन प्रशासन स्तर पर हर विभाग के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ऊपर से निचले स्तर तक इतना फैला हुआ है कि बहुत सारे लोग तो यह मानने को तैयार नहीं होते हैं कि कोई सरकार,कोई सीएम,कोई अधिकारी इसे पूरी तरह समाप्त कर सकता है। जनता का वास्ता तो हर क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी से रोज पड़ता है, शासन व प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार का खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ता है इसलिए किसी भी दफ्तर से लेकर विभाग में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है,आम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए वह किसी सरकार से यह उम्मीद नहीं करती है कि वह शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकती है। जनता ने ऐसी सरकारों को देखा है जो खुद जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है, वहां भ्रष्टाचार का बढ़ावा देती है और पार्टी फंड के लिए पैसा जुगाड़ करती है। जनता ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार को देखा है इसलिए उसे यह अच्छा लगता है कि कोई सरकार राज्य में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त भले न कर सके लेकिन कम करने की कोई कोशिश हो सकती है तो वह कम करने की कोशिश करती है,उस क्षेत्र की व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करती है।

जहां भी सबसे ज्यादा नगद पैसा होता है,वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जहां भी नगदी का काम होता है,वहां भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की जरूरत रहती है लेकिन कमाई ऊपर से नीचे तक होती रहती है तो ऐसा कोई करना नहीं चाहता है, यही वजह है कि भ्रष्टाचार होगा तो सबकी कमाई होती है,इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में ऊपर से नीचे तक आम सहमति रहती है,इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं जाती है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। शराब दुकानों में शराब की ज्यादातर खरीदी नगद की होती आई है। इसलिए यहां कई तरह से भ्रष्टाचार किया जाता रहा है। सबसे आसान होता है कि तय कीमत से ज्यादा पैसे लेना, मिलावटी शराब बेचना, अवैध शराब बेचना। हाल ही में एक खबर आई थी कि एक आबकारी निरीक्षक जो भानुप्रतापपुर क्षेत्र की प्रभारी थी, उसके क्षेत्र में अवैध शराब बनाने का सामान मिला था। उसे लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया है। इसी मामले में कर्तव्य में लापरवाही के चलते सहायक जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। इसी तरह महासमुंद के एक आबकारी उपनिरीक्षक को शराब दुकान में 190 की शराब 200 में बेचने के कारण प्रकरण दर्ज कर निलंबित कर दिया गया है।महासमुंद क्षेत्र की तुमाडबरी शराब दुकान में तय कीमत से ज्यादा पैसे लेने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी को सात दिन में जवाब मांगा गया है इसी तरह महासमुंद के एक अन्य सहायक जिला आबकारी अधिकारी को शराब दुकान में तय कीमत से ज्यादा पैसा लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आबकारी विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक छोटे अधिकारी तक जानते हैं कि शराब दुकानों में हो रहे इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन शराब दुकानों में हो रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर अब तक अचानक शराब दुकान पहुंच कर जांच की जाती थी और ज्यादा पैसे में शराब बिकने पर अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता या नोटिस जारी कर दिया जाता था। पिछले दस साल से आनलाइन भुगतान की सुविधा हमारे देश व राज्यों में है।शराब दुकानों में शराब का पैसा आनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था की जाती तो ज्यादा पैसे लेकर शराब बेचने के नाम पर जो करोड़ों का भ्रष्टाचार पिछले दस साल में हुआ उसे रोका जा सकता था, ऐसा नहीं किया गया, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर जैसी कार्रवाई बरसों से हो रही थी, वही कार्रवाई यह जानते हुए भी की जा रही थी कि इससे शराब दुकानों में होने वाला भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है।शासन प्रशासन के जो अधिकारी व कर्मचारी होते हैं वह नई नई तकनीक के अक्सर विरोधी होते हैं क्योंकि तकनीक के कारण वह पहले की तरह भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह तकनीक का प्रयोग अपने क्षेत्र में जल्द करने के पक्षधर नहीं होते हैं इस इसमें जितनी देरी हो सकती है, करते हैं।

राज्य में पिछली सरकार की तुलना में साय सरकार की तारीफ तो इस बात के लिए करनी होगी कि उसने इस बात समझ लिया कि किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकना है या सुधार करना है तो तकनीक का प्रयोग करके ही किया जा सकता है। साय सरकार कई क्षेत्रों में तकनीक का प्रयोग कर सुधार कर रही है और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।शराब दुकानों में साय सरकार ने अब नगद की जगह डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करके यहां होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया है।साय सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक अब एक अक्टूबर 2026 से राज्य की 22 जिलों की 49 प्रीमियम शराब दुकानों में अब नगदी लेन देने बंद हो जाएगा, जिसे भी शराब खरीदनी है उसे डिजिटल भुगतान करना होगा, इससे शराब दुकान के कर्मचारी ज्यादा पैसा नहीं ले सकेंगे ।सीएसएमसीएल के संचालक मंडल की 7 अगस्त को हुई बैठक के बाद यह निर्देश 22 जिलों की 49 प्रीमियम दुकानों के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें रायपुर की 13 दुकाने,दुर्ग की 6,महासमुद की 3,बालोद की 3,बिलासपुर की ३,राजनांदगांव की 2,कांकेर की 2,जांचगीर-चांपा की 2 और रायगढ़ की 2 दुकानें शामिल हैं।

शराब दुकानों में कैशलेस व्यवस्था होने से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी,शराब बिक्री की व्यवस्था में पारदर्शिता बढेगी, बिक्री व लेनदेन की निगरानी आसान होगी। शराब खरीदने वाले ग्राहक अपने मोबाइल से दुकान में उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन पर भुगतान करेंगे तो लेनदेन डिजिटल होने के कारण उसका रिकार्ड भी उपलब्ध रहेगा ।इससे शराब दुकाने के कर्मचारी अब तक जो भ्रष्टाचार कर रहे थे वह नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों से निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे लेने की जो शिकायत सबसे ज्यादा रहती थी,वह शिकायत अब खत्म हो जाएगी। प्रत्येक डिजिटल भुगतान का रिकार्ड रहने से विभाग जरूरत पड़ने पर उसकी जांच भी कर सकता है। साय सरकार ने आने के बाद कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुधार की जरूरत थी, वह सुधार अब हो रहे हैं ।इससे भ्रष्टाचार की शिकायते कम हुई हैं तथा आने वाले दिनों में और कम होंगी। ऐसा होता है तो राज्य के वे लोग जो यह मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, वह उम्मीद कर सकेंगे कि भ्रष्टाचार को कम करते करते एक दिन समाप्त भी किया जा सकता है।

2024 की कहानी दोहराएगी सपा या योगी फिर लिखेंगे सत्ता की पटकथा

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सत्ता की लड़ाई अब धीरे-धीरे अपने असली रूप में सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार की उपलब्धियों को चुनावी वोट में बदलने की है, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले अप्रत्याशित बढ़त को विधानसभा की सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन मॉडल और अखिलेश यादव का पीडीए गठजोड़ आमने-सामने है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन आगे है, बल्कि यह है कि 2024 में बदला सामाजिक समीकरण 2027 में कितना टिकाऊ साबित होता है।

403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2022 का जनादेश भाजपा के पक्ष में बेहद स्पष्ट था। भाजपा ने 255 सीटें जीतीं और समाजवादी पार्टी 111 सीटों तक पहुंची। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस तस्वीर को पूरी तरह झकझोर दिया। भाजपा 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। भाजपा का मत प्रतिशत करीब 41 प्रतिशत था और सपा का लगभग 34 प्रतिशत। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सीटों में उसका प्रभाव असाधारण रहा। यही वजह है कि भाजपा 2027 को 2024 की भरपाई का चुनाव मानकर चल रही है। भाजपा की रणनीति का पहला हथियार शासन का रिपोर्ट कार्ड है। पार्टी 2012 से 2017 के सपा शासन और 2017 के बाद योगी सरकार के बीच सीधी तुलना करने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा, बिजली, गरीब कल्याण और बुनियादी ढांचा इस तुलना के प्रमुख आधार होंगे।

भाजपा का तर्क होगा कि 2017 के बाद प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई की नीति बदली और शासन में प्रशासनिक कठोरता आई ।सरकार के आंकड़े भी इस दावे को राजनीतिक ताकत देते हैं। 2017 के बाद हजारों अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई और अरबों रुपये की संपत्तियों की जब्ती को भाजपा चुनावी प्रचार में प्रमुखता से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यहीं विपक्ष का सवाल भी खड़ा होगा। क्या कठोर कार्रवाई का मतलब अपराध पूरी तरह खत्म हो जाना है? क्या थाने से लेकर अदालत तक आम आदमी को समान सुरक्षा और न्याय मिल रहा है? 2027 में भाजपा को आंकड़ों के साथ इन सवालों का जवाब भी देना होगा ।विकास भाजपा का दूसरा बड़ा स्तंभ होगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का विस्तार, नए हवाई अड्डे, औद्योगिक परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था, एक जनपद एक उत्पाद और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां सरकार की उपलब्धियों में गिनी जाएंगी। 2026 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान भी विकास की प्राथमिकता को दशार्ता है। सरकार निवेश प्रस्तावों और संभावित रोजगार के बड़े आंकड़े पेश कर सकती है।

लेकिन चुनावी राजनीति में प्रस्ताव और परिणाम के बीच का अंतर बहुत मायने रखता है। निवेश के हजारों प्रस्ताव होना अलग बात है और उन प्रस्तावों से जमीन पर कारखाने और रोजगार पैदा होना अलग। युवा पूछेगा कि नौकरी कहां है, किसान पूछेगा कि आमदनी कितनी बढ़ी, व्यापारी पूछेगा कि कारोबार कितना सुधरा और परिवार पूछेगा कि महंगाई के बीच उसकी बचत कितनी बची। इसलिए भाजपा के लिए विकास का असली रिपोर्ट कार्ड सरकारी विज्ञप्ति नहीं, मतदाता का अनुभव होगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत 2024 का सामाजिक संदेश है। सपा ने पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच देने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव में उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। अब पार्टी दलित समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और सामाजिक न्याय के सवाल को चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संविधान, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवालों को भाजपा के खिलाफ व्यापक सामाजिक गोलबंदी में बदलने की कोशिश होगी। लेकिन पीडीए की राह भी आसान नहीं है।

यादव और मुस्लिम मतदाताओं का पारंपरिक आधार सपा के साथ रहा है, लेकिन गैर यादव पिछड़ों और दलितों को स्थायी रूप से जोड़ना अलग चुनौती है। 2024 में किसी मुद्दे या राजनीतिक परिस्थिति के कारण बना गठबंधन 2027 में अपने आप कायम रहेगा, यह मान लेना सपा के लिए जोखिम भरा होगा। उसे टिकट वितरण से लेकर संगठन तक वास्तविक भागीदारी दिखानी होगी। भाजपा इसी कमजोर कड़ी पर चोट करेगी। गैर यादव पिछड़े, गैर जाटव दलित, सवर्ण, महिलाएं और छोटे सामाजिक समूह उसके सामाजिक समीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पार्टी का संदेश होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जाति देखकर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर दिया गया। मुफ्त राशन, आवास, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक बनाए जा सकते हैं। बूथ स्तर पर लाभार्थियों से संपर्क इसी रणनीति का हिस्सा है। 2024 के झटके के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके सामाजिक आधार में दरार कहां और क्यों आई। यदि वह केवल हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के सहारे आगे बढ़ती है और रोजगार, महंगाई तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवालों को पीछे छोड़ देती है, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा।

भाजपा के लिए हिंदुत्व उसका वैचारिक आधार है, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए उसे शासन के प्रदर्शन की विश्वसनीयता भी साबित करनी होगी ।अखिलेश के सामने भी उतनी ही कठिन परीक्षा है। पीडीए को सत्ता विरोधी भावना से जोड़ना आसान है, लेकिन 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना और अलग-अलग सामाजिक समूहों को साथ रखना कठिन। सपा को यह बताना होगा कि सरकार बदलने के बाद रोजगार, कानून व्यवस्था, निवेश, किसान और गरीबों के लिए उसकी ठोस नीति क्या होगी। केवल भाजपा विरोधी राजनीति से सत्ता की सीढ़ी पूरी नहीं होगी ।यही कारण है कि 2027 की लड़ाई में असली मुकाबला दो नारों का नहीं, दो राजनीतिक मॉडलों का होगा। भाजपा शासन, सुरक्षा, विकास और हिंदुत्व को जोड़कर जनता के सामने जाएगी।

सपा सामाजिक न्याय, पीडीए और प्रतिनिधित्व को अपना आधार बनाएगी। 2022 का जनादेश भाजपा की ताकत दिखाता है और 2024 का परिणाम उसकी कमजोर कड़ियां। आखिरकार उत्तर प्रदेश का मतदाता दोनों से एक ही सवाल पूछेगा काम क्या किया और आगे क्या करेंगे। भाजपा के पास नौ साल का शासन रिकॉर्ड है, सपा के पास सत्ता में लौटने की राजनीतिक बेचैनी और 2024 का आत्मविश्वास। अगर भाजपा 2024 की चोट से सबक लेकर अपने सामाजिक समीकरण को फिर मजबूत कर लेती है, तो योगी की राह आसान होगी। अगर अखिलेश पीडीए को जातीय गठजोड़ से आगे बढ़ाकर व्यापक सामाजिक गठबंधन बना लेते हैं, तो मुकाबला बेहद कठिन होगा। 2027 में फैसला इसी बात से होगा कि कौन दल आंकड़ों, संगठन और सामाजिक भरोसे को एक साथ चुनावी ताकत में बदल पाता है।

तेल के रास्ते बंद, सऊदी बेबस, ईरान के हाथ में दुनिया की नब्ज

अजय कुमार

मध्यपूर्व की इस जंग में अब असली निशाना सिर्फ जमीन, बंदरगाह या सैन्य अड्डे नहीं हैं। असली निशाना तेल के रास्ते हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमले ने दुनिया को फिर याद दिला दिया है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था कितनी नाजुक है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है और इसकी अधिकतम क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। हमले के बाद इसका संचालन रोकना पड़ा ।यही इस हमले का सबसे बड़ा अर्थ है। सऊदी अरब ने ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन इसलिए बनाई थी कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भरता कम हो। सामान्य परिस्थितियों में होर्मुज से प्रतिदिन करीब दो करोड़ बैरल तेल और तेल उत्पाद गुजरते हैं।

अब जब होर्मुज युद्ध के कारण दबाव में है और सऊदी का वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग भी चोटिल हो गया, तो बाजार में डर लौटना स्वाभाविक है ।कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर के पार जाना इसी डर की कीमत है। ब्रेंट 109 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। बाजार में भविष्य की कमी की आशंका आज की कीमत बढ़ाती है। यदि पाइपलाइन लंबे समय तक बंद रहती है, तो यानबू से निर्यात प्रभावित होगा और सऊदी अरब को आपूर्ति की नई गणित बनानी पड़ेगी। जिस पाइपलाइन से हाल में लगभग 40 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल गुजर रहा था, उसका रुकना वैश्विक बाजार के लिए बड़ा झटका है। यह वैश्विक आपूर्ति का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा है ।सऊदी अरब की मुश्किल यह है कि उसके सामने सिर्फ एक रास्ते का संकट नहीं है। पूर्व में होर्मुज है, दक्षिण में बाब अल-मंदब है और पश्चिम में लाल सागर। हूती हमलों ने बाब अल-मंदब और लाल सागर की जहाजरानी को जोखिम में डाल रखा है। होर्मुज में ईरान के साथ टकराव ने दूसरा बड़ा रास्ता असुरक्षित कर दिया। अब वह पाइपलाइन भी बंद है जिसे इन्हीं समुद्री जोखिमों का विकल्प माना जाता था।

इस घटना को सिर्फ सऊदी अरब पर हमला मानना भूल होगी। तेल की कीमत केवल उत्पादन से तय नहीं होती; परिवहन, बीमा, भंडार और जोखिम भी उसकी कीमत बनाते हैं। पाइपलाइन बंद होने का मतलब यह नहीं कि दुनिया से अचानक लाखों बैरल तेल गायब हो गया। मतलब यह है कि उपलब्ध तेल को बाजार तक पहुंचाना कठिन और महंगा हो गया ।भारत के लिए असली चिंता यहीं से शुरू होती है। घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की हर छलांग को उसी दिन नहीं दिखातीं। तेल कंपनियां पुराने स्टॉक और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर झटका कुछ समय रोक सकती हैं। लेकिन यदि कच्चा तेल लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर रहता है, तो दबाव बढ़ेगा। भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपये पर दबाव आएगा और महंगे परिवहन का असर खाद्य पदार्थों से लेकर उद्योग तक दिखाई देगा ।इस संकट का राजनीतिक चेहरा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का रक्षा समझौता किया है। यदि सऊदी के तेल ढांचे पर लगातार हमले होते हैं, तो सवाल उठेगा कि सुरक्षा साझेदारी केवल राजनीतिक बयान है या जरूरत पड़ने पर सैनिक, हथियार और वायु रक्षा भी सामने आएगी।

आज सऊदी अरब और हूती एक-दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1934 में सऊदी-यमन युद्ध के बाद असीर और नजरान जैसे इलाके सऊदी नियंत्रण में आए। फिर 1962 में यमन की राजशाही गिरने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने गणतांत्रिक सरकार के समर्थन में सेना भेजी। एक समय यमन में लगभग 70 हजार मिस्री सैनिक मौजूद थे। सऊदी अरब ने जवाब में जैदी राजशाही समर्थकों को पैसा, हथियार और मदद दी। जिन जैदी परंपराओं से आगे चलकर हूती आंदोलन निकला, उनके पूर्ववर्तियों को कभी सऊदी समर्थन मिला था ।आधुनिक हूती आंदोलन ने बाद में सऊदी और यमनी सत्ता दोनों के लिए चुनौती पैदा की। 2004 से 2009 के बीच कई युद्ध हुए और 2009 में सऊदी सेना सीधे संघर्ष में उतरी। पहाड़ी भूगोल और गुरिल्ला युद्ध ने सऊदी सेना को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। 2019 में हूतियों के हमले ने इसी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया था।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की रणनीति क्या है। यदि होर्मुज को दबाव में रखकर और उसके समर्थक गुटों के जरिए लाल सागर तथा तेल ढांचे पर खतरा बढ़ाकर वह अमेरिका और उसके सहयोगियों की आर्थिक लागत बढ़ाता है, तो युद्ध का मैदान मिसाइलों से निकलकर वैश्विक बाजार में पहुंच जाता है। महंगा तेल अमेरिका के लिए आर्थिक ही नहीं, घरेलू राजनीतिक संकट भी बन सकता है ।यहीं ईरान की परोक्ष युद्ध रणनीति का महत्व समझना होगा। ईरान पर सीधे हमला करना एक बात है, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में मौजूद सशस्त्र गुटों के जरिए ऊर्जा ढांचे को दबाव में लाना दूसरी। इससे जवाबदेही धुंधली रहती है और विरोधी को एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ते हैं। यही वजह है कि किसी हमले की जिम्मेदारी सामने न आने के बावजूद उसके रणनीतिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अब। सऊदी अरब के लिए खतरा अब केवल सीमा पार से आने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि किसी भी दिशा से आने वाला छोटा ड्रोन भी है।

अगर पाइपलाइन ही निशाना बन जाए, तो होर्मुज का विकल्प मौजूद होकर भी कमजोर पड़ जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा किसी सैन्य अड्डे जैसी नहीं की जा सकती। हर किलोमीटर पर सैनिक तैनात करना संभव नहीं। यही इस हमले की असली रणनीतिक ताकत है एक छोटा ड्रोन हजारों किलोमीटर की ऊर्जा रणनीति को अस्थायी रूप से पंगु बना सकता है ।आने वाले दिनों में निर्णायक बात यह होगी कि सऊदी अरब पाइपलाइन कितनी जल्दी बहाल करता है और लाल सागर तथा होर्मुज की स्थिति कितनी सुधरती है। अगर एक रास्ता बंद, दूसरा असुरक्षित और तीसरा हमले की जद में रहा, तो 120 डॉलर का तेल भी असंभव नहीं होगा। तब संकट केवल पेट्रोल-डीजल की कीमत का नहीं रहेगा। आयात बिल, महंगाई, मुद्रा और वैश्विक विकास सभी पर असर पड़ेगा। सौ बात की एक बात यही है मध्यपूर्व की जंग अब सीमाओं के भीतर नहीं रही। उसकी असली लपटें तेल के रास्तों तक पहुंच चुकी हैं।

हिमालयी पानी बम

नेपाल की प्रलयंकारी बाढ़ ने हिमालयी सीमा में बसे देशों की सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग से निरंतर बनती हिमनद झीलों के भयावह खतरों के प्रति सचेत किया है। यह संकट एक देश की सीमाओं से परे पूरे हिमालयी क्षेत्रों में व्याप्त है। ऐसे में निगरानी तंत्र को मजबूत करने और इसके दायरे में आने वाले देशों, राज्यों और शहरों को समय रहते सूचना देने के लिए एक प्रभावी सिस्टम विकसित करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। साल 2013 में केदारनाथ त्रासदी से उपजी तबाही की तस्वीरें आज भी भारतीय जनमानस की स्मृतियों में ताजा हैं। पूर्वी हिमालय स्थित सिक्किम में भी चालीस हिमनद झीलों का पता चला है। चिंता की बात यह है कि इसमें से सोलह को अधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी के एक अध्ययन में लगातार विस्तार ले रही नौ ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई थी। कमोबेश उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है जो जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से पिघलते ग्लेशियरों से उपजे संकट की ओर ध्यान खींचती हैं। आईआईटी के अध्ययन के जरिये तीन हजार पांच सौ मीटर से ज्यादा ऊंचाइयों पर दो हजार से अधिक झीलों का पता चला है। बताया जाता है कि ये झीलें तेजी से बन रही हैं और इनकी संख्या एक दशक पहले की तुलना में 710 अधिक हो गई है। इनका क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। यह वृद्धि 28 फीसदी बढ़ी बतायी जाती है, जिसके चलते कई रिहायशी इलाकों, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और अनेक पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर टूटने और चट्टानें खिसकने से ये झीलें कितना भयावह रूप ले सकती हैं, उसकी बानगी 26 अगस्त को नेपाल में हुई तबाही में नजर आई है। वहां आज भी हजारों लोग लापता हैं। चट्टानों, पानी, कीचड़ आदि का जो सैलाब घाटियों से गुजरा है, उसने बस्तियों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों की अभी भी तलाश जारी है।

नेपाल हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और बताया है कि ऊंचाई वाली जगहों में झील में बर्फ-चट्टानों के गिरने के बाद इन झीलों को रोकने वाले अवरोध टूटते हैं, जिससे नीचे वाले इलाकों में बेहद तीव्र गति से तबाही आ सकती है। दरअसल, लगातार गर्म होते हिमालय में ग्लेशियरों का पीछे हटना, झीलों का बढ़ना, भूस्खलन और अतिवृष्टि की घटनाएं आपस में मिलकर भयावह स्थिति पैदा करती हैं, जिसका मुकाबला सामान्य आपदा प्रबंधन के उपायों से नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए ग्लेशियर झीलों के फटने का इंतजार नहीं किया जा सकता। जमीनी स्तर पर निगरानी के साथ ही उपग्रहों के जरिये भी इन झीलों पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। रियल-टाइम अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा निकासी रास्तों को चिन्हित करने की जरूरत भी है। नीचे नदियों के किनारे बसी बस्तियों व मैदानी इलाकों में बचाव के तौर-तरीकों का नियमित अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुलों, पनबिजली परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचों की जांच करके उन्हें अधिक सुरक्षित बनाने की भी जरूरत है। साथ ही इन से जुड़े संभावित खतरों का समय रहते मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में विकास के नये मॉडल पर भी विचार करने की जरूरत है, जो हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता के अनुरूप हो।

जब हुनर को मंच और अनुभव को अवसर मिलता है, तब बदलता है भविष्य

एनएसटीआई से मिलेगी कौशल को नई पहचान, 45 वर्ष की आयु सीमा से अनुभव को लाभ-मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में अवसरों का विस्तार

एल.डी. मानिकपुरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायुपर

छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक ध्यान के कटोरे के रूप में रही है। खेतों में लहलहाती फसलें प्रदेश की समृद्धि की कहानी कहती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ छत्तीसगढ़ ने विकास की अपनी यात्रा में नए आयाम जोड़े हैं। अब कृषि के साथ उद्योग, तकनीक के साथ कौशल और रोजगार के साथ उद्यमिता भी प्रदेश की नई पहचान बन रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश के युवा और अनुभवी मानव संसाधन हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हालिया निर्णय इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। एक ओर नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) की स्थापना होने से युवाओं को आधुनिक कौशल का मंच मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष किया जाना अनुभव और क्षमता को नए अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है।

सपनों को डिग्री के साथ हुनर भी चाहिए

आज का युवा केवल शिक्षा नहीं, रोजगारपरक कौशल चाहता है। उद्योगों की बदलती जरूरतों के बीच ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम तेंदुवा में एनएसटीआई की स्थापना के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में हर वर्ष करीब एक हजार तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों में लगभग तीन हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। हजारों युवाओं के सपनों से जुड़ा अवसर है। इससे कोई तकनीकी कौशल हासिल करेगा, कोई उद्योग से जुड़ेगा, तो कोई अपना उद्यम शुरू कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

कौशल से रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह

एनएसटीआई की स्थापना होने से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। आज कौशल केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है। गांव और कस्बे के युवा को भी उद्यमशील बनने का अवसर मिलेगा। एक प्रशिक्षित युवा नौकरी तलाशने वाला बनने के साथ नौकरी देने वाला उद्यमी भी बन सकता है। यही कौशल से उद्यमिता और रोजगार से आत्मनिर्भरता की यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं से अक्सर कहते हैं कि ऐसा कार्य करें जो युवाओं को रोजगार देने वाला बने, ताकि उनकी नई पहचान बन सके।

उम्र बढ़ी तो अवसरों का दायरा भी बढ़ा

अधिकतम आयु सीमा को 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय उन लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, जिनके पास अनुभव, कार्यकुशलता और जिम्मेदारियों का व्यावहारिक ज्ञान है। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है और अनुभव किसी भी व्यवस्था की महत्वपूर्ण पूंजी है। वर्षों तक काम कर चुके लोगों ने व्यवस्था को करीब से समझा है और चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे अनुभव का बेहतर उपयोग नई जिम्मेदारियों में किया जाना संस्थाओं को अधिक सक्षम बना सकता है।

युवा ऊर्जा और अनुभवी हाथ साथ चलें

विकास की मजबूत तस्वीर तब बनती है, जब युवा ऊर्जा और अनुभवी सोच साथ आती है। युवा नई तकनीक और नए विचार लाते हैं, जबकि अनुभवी वर्ग व्यावहारिक समझ और परिस्थितियों से निपटने का अनुभव देता है। एनएसटीआई युवाओं के हुनर को मंच देगा, तो आयु सीमा में वृद्धि अनुभवी वर्ग की क्षमता को अवसर। दोनों निर्णय मिलकर प्रदेश की मानव पूंजी को मजबूत करने की दिशा दिखाते हैं।

छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल उसकी प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की क्षमता से तय होगा। जब हुनर को मंच, अनुभव को अवसर और सपनों को सही दिशा मिलेगी, तब विकास आंकड़ों से निकलकर लोगों की जिंदगी में दिखाई देगा। यही नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, जहां कौशल से रोजगार, अनुभव से अवसर और अवसर से आत्मनिर्भरता की राह तैयार हो रही है। इसी तरह के निर्णयों से छत्तीसगढ़ सरकार सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

बीएसएनएल अधिकारी-कर्मचारी मोर्चा के संयुक्त केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देशभर में आंदोलन का किया आगाज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

बीएसएनएल अधिकारी-कर्मचारी मोर्चा के संयुक्त केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देशभर में आंदोलन का आगाज बुधवार को प्रदर्शन और नारेबाजी के साथ हुआ। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित बीएसएनएल कार्यालय के मुख्य द्वार पर अधिकारी-कर्मचारियों ने सभा आयोजित कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

सभा को संबोधित करते हुए बीएसएनएलईयू दुर्ग के आर.एस. भट्ट ने कहा कि सरकार तीसरे वेतनमान को लागू करने के मामले में अफोर्डेबिलिटी (वहनीयता) की शर्त के तहत घाटे में चल रही कंपनी के कर्मचारियों को लाभ देने से इंकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने, पंचायतों एवं स्कूलों तक संचार सेवाएं पहुंचाने सहित विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी जाती है। इन परियोजनाओं में होने वाले आर्थिक नुकसान का भार कंपनी पर पड़ता है और इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भट्ट ने कहा कि यदि बीएसएनएल सरकारी परियोजनाओं से हाथ खींच ले तो डिजिटल इंडिया के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि निजी दूरसंचार कंपनियां सरकारी योजनाओं में इसी तरह के नुकसान का भार उठाने के लिए आगे नहीं आतीं। उनके अनुसार बीएसएनएल की मौजूदगी ने निजी दूरसंचार कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क वसूली के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार निजी दूरसंचार सेवाओं को लेकर यूनियन पदाधिकारियों ने पूर्व में एकाधिकार की आशंका जताई थी, उसी तरह बीएसएनएल को कमजोर किए जाने से दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में निजी दूरसंचार कंपनियों ने उपभोक्ताओं का दोहन किया है। सहायक महाप्रबंधक लोकेश ठाकुर ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष करने पर ही उनका अधिकार मिल सकता है। उन्होंने आंदोलन के आगामी चरणों में वेतन कटौती जैसी कार्रवाई के लिए भी सभी कर्मचारियों से तैयार रहने का आह्वान किया।

उपमंडल अभियंता राव ने कहा कि बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन आयोग का अंतिम लाभ वर्ष 2007 में मिला था। उन्होंने उस समय और वर्तमान में सोने की कीमतों में आए अंतर का उदाहरण देते हुए कहा कि महंगाई और जीवन-यापन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों को वेतन संबंधी अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बीएसएनएल के लगभग चार लाख कर्मचारी और पेंशनर अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने सभी से आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। प्रदर्शन में पी.के. वर्मा, महेश, सचिन सोनी, संतोष सोनी, महेश उइके, बी.बी. देवांगन, गोमती राय, संदीप श्रीवास्तव, गीतेश पटेल, दिग्विजय सिंह ठाकुर सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीएसवीटीयू भिलाई में खेल समिति-2026-27 का किया गया गठन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए खेल गतिविधियों हेतु नई विश्वविद्यालय खेल समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन 16 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से किया गया।

समिति के पदेन अध्यक्ष कुलपति डॉ. अरुण अरोरा होंगे। समिति में संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर, संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त खेल क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, खेल विशेषज्ञ तथा शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति में बीआईटी दुर्ग के प्राचार्य डॉ. अनुप मिश्रा एवं शास.कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर की प्राचार्य डॉ. वर्षा चौरसिया को संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य वर्ग से सदस्य बनाया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से सहायक प्राध्यापक - डॉ. हरीश घृतलहरे, विवेक मिश्रा एवं डॉ. आर.जी. ब्रजेश सदस्य हैं। वहीं संबद्ध महाविद्यालयों से विजय शुक्ला, के.पी. यादव एवं सोमेश यादव को सदस्य बनाया गया है।

कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त सदस्यों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य राजेश चौहान, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व सदस्य सुश्री रेणुका यादव एवं वॉलीबॉल के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी ख्वाजा अहमद शामिल हैं। खेल विशेषज्ञ वर्ग में डॉ. मेजर सिंह मनसा पॉलीटेक्निक भिलाई एवं ओंकार जैसवाल एलसीआईटी बिलासपुर तथा शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक वर्ग में कोंडल राव बीआईटी दुर्ग एवं पुरूषोत्तम रात्रे आरआईटी रायपुर को सदस्य बनाया गया है।

विश्वविद्यालय टीम के कप्तान वर्ग से सुश्री किरात कौर आरसीईटी आर 1 भिलाई (गतका महिला वर्ग अखिल भारतीय अंतर विवि प्रतियोगिता 2025-26 में कांस्य पदक विजेता) एवं सुश्री रुपाली साहू एलसीआईटी बिलासपुर (किक बॉक्सिंग महिला वर्ग अखिल भारतीय अंतर विवि प्रतियोगिता 2024-25 में कांस्य पदक विजेता) को समिति में सदस्य बनाया गया है। वहीं कुलसचिव डॉ. राजेश लालवानी पदेन सदस्य सचिव तथा विश्वविद्यालय खेल विभाग के भारसाधक किशोर कुमार भारद्वाज समिति के पदेन सदस्य होंगे।

अधिसूचना में विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 26 के अनुसार यह भी उल्लेखित है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वे दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। कप्तान वर्ग का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा। खेलकूद गतिविधियों एवं वित्तीय अनुशासन के लिए पृथक से 3 से 5 उपसमितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय की इस नई खेल समिति से सत्र 2026-27 में खेल गतिविधियों के अधिक व्यवस्थित संचालन तथा विश्वविद्यालय की खेल टीमों की तैयारियों को संस्थागत रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है।

खास खबर

सांसद दिलीप कुमार राय से पार्षद मनीष यादव ने की सौजन्य मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद एवं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनीष यादव (बंटी) ने ओडिशा से राज्यसभा सांसद, मेफेयर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के संस्थापक एवं चेयरमैन तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप कुमार राय से सौजन्य एवं आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसद राय का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं विकासात्मक विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। पार्षद मनीष यादव ने कहा कि सांसद दिलीप कुमार राय के लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, उद्यमशील सोच और समाज के प्रति दृष्टिकोण से उन्हें काफी कुछ सीखने का अवसर मिला।

श्री यादव ने कहा कि वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तित्व के साथ संवाद करते हुए यह अनुभव होता है कि जब अनुभव नई सोच और जनसेवा की ऊर्जा से जुड़ता है, तो भविष्य की अनेक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद राय का स्नेह, सहजता और मार्गदर्शन उनके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आत्मीय मुलाकात आने वाले समय में सार्थक विचारों, सकारात्मक प्रयासों और जनहित से जुड़ी नई संभावनाओं के लिए एक मजबूत आधार बनेगी।

आगामी त्योहारों को लेकर बिलासपुर पुलिस सख्त, गुंडा-निगरानी बदमाशों की परेड ली

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

आगामी त्योहारों गणेश पूजा, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस ने जिले के सभी गुंडा और निगरानी बदमाशों की परेड ली। DIG एवं SSP रजनेश सिंह के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्र के बदमाशों को तलब कर उनके वर्तमान क्रियाकलापों की समीक्षा की। बदमाशों को त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, परिवार के साथ शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की समझाइश दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि उपद्रव या शांति भंग करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर बाउंड ओवर किया जाएगा।

तारा कोल ब्लॉक नीलामी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वार

आदिवासियों के जीवन आधार जंगल को भाजपा ने नीलाम किया

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तारा क्षेत्र के जंगल आदिवासियों के जीवन आधार हैं, भाजपा सरकार ने उसे नीलाम कर दिया। बघेल ने बताया कि साय सरकार ने खुद 11 दिसंबर 2025 को केंद्र को पत्र लिखकर नीलामी की अनुशंसा की, जबकि कांग्रेस सरकार ने 23 जून 2023 को तारा सहित 9 ब्लॉकों को नीलामी से अलग रखने का पत्र लिखा था। विधानसभा ने 2022 में सर्वसम्मति से हसदेव में नया आवंटन न करने का प्रस्ताव पारित किया था। 19 अक्टूबर 2023 को केंद्र ने तारा को डी-नोटिफाई भी किया था।

उन्होंने कहा कि तारा ब्लॉक 5000 एकड़ में है, जिसमें 4000 एकड़ घना जंगल है। 10 लाख से अधिक पेड़ कटेंगे। लेमरू एलीफेंट रिजर्व के आसपास खनन से हाथियों के कॉरिडोर पर असर पड़ेगा। यह ब्लॉक अडानी इंटरप्राइजेज की सहयोगी कंपनी को मिला है। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी साय सरकार अडानी के हित में काम कर रही है।

PSC घोटाले पर भी साधा निशाना

बघेल ने कहा कि 2024 और 2025 में PSC परीक्षा में गड़बड़ी हुई। सही-गलत उत्तर पर बराबर नंबर, कहीं गलत को ज्यादा नंबर दिया गया। 265 पदों पर 795 को इंटरव्यू में बुलाना था, सिर्फ 608 को बुलाया गया। मूल्यांकन अपात्र शिक्षकों से कराया गया। मांग की कि इंटरव्यू स्थगित कर कॉपियां सार्वजनिक की जाएं और पुनर्मूल्यांकन हो।

पीएससी में गड़बड़ी का आरोप: कांग्रेस ने कहा- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

छत्तीसगढ़ PSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि PSC युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। दीपक बैज ने कहा कि 2024 में भी इंटरव्यू में 95 अभ्यर्थी कम लिए गए थे। मूल्यांकन अपात्र स्कूली शिक्षकों से कराया गया। गड़बड़ी के बावजूद रीता सांडिल्य को कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष बना दिया गया, इससे सरकार का संरक्षण स्पष्ट है।

कांग्रेस के आरोप

- 2025 में 265 पदों के लिए 795 (1:3) को इंटरव्यू में बुलाना था, सिर्फ 608 को बुलाया गया। 187 बच्चों को न्यूनतम अंक नहीं लाने का हवाला दिया गया।
- 2024 की मुख्य परीक्षा की दो कॉपियों में मूल्यांकन में भारी अंतर मिला। एक ही सही उत्तर पर एक को 0 और दूसरे को 2 अंक दिए गए।
- भक्तिन माता राजिम के सही उत्तर पर 3.5 अंक, जबकि गलत उत्तर लिखने वाले को 1.5 अंक मिला।
- होमरूल लीग और घरेलू हिंसा जैसे सवालों में भी सही-गलत को बराबर नंबर दिए गए।
- बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण के सही उत्तर पर एक को 0.5 और दूसरे को 1.5 अंक।

मांग -इंटरव्यू स्थगित किया जाए, सभी की कॉपियां सार्वजनिक हों, पुनर्मूल्यांकन हो और 1:3 के नियम का पालन हो।

शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने दुर्ग नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर में व्याप्त विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल एवं नगर पालिक निगम दुर्ग के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त लीना कोसम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शहर की मूलभूत सुविधाओं और निगम की कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने आयुक्त को अवगत कराया कि शहर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की कार्यप्रणाली की स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्षी पार्षदों के साथ-साथ सत्ता पक्ष के पार्षद भी अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को बिजली, पानी, सफाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने, शहर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने, कचरा निष्पादन एवं साफ-सफाई व्यवस्था नियमित करने, बार-बार उत्पन्न हो रहे जल संकट का स्थायी समाधान कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित प्रबंधन की मांग की।

इसके अलावा चंडी मंदिर से उरला, गया नगर, रामनगर होते हुए राम मैरिज गार्डन तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के तत्काल नवनिर्माण की मांग भी की गई। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधीश एवं लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता को भी सौंपे जाने की जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को सुनने के बाद निगम आयुक्त श्रीमती लीना कोसम ने संबंधित विषयों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर उप नेता प्रतिपक्ष विजयंत पटेल, संगठन प्रभारी महामंत्री रायसिंह दीकोला, पार्षद संगीता सोनी, दीपक साहू, हामिद खोखर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद कपूर ताम्रकार, गुरदीप सिंह भाटिया, सुनीत घोष, देव सिन्हा, मनीष सोनवानी, निखिल खिचड़िया, अमोल जैन, भीमसेन पासी अली, चिराग शर्मा, गौरव उमरे, हिमांशु शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित

वरिष्ठ नागरिक मंच कोहका का 12वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से सम्पन्न

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वरिष्ठ नागरिक मंच कोहका का 12वां स्थापना दिवस सियान सदन, टाटा लाइन, कोहका में सम्पन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा श्री गणपति एवं भारत माता के छायाचित्रों पर माल्यार्पण और मंगलदीप प्रज्वलन से किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाष साव (संचालक, होटल अमित इंटरनेशनल, भिलाई) थे। विशेष अतिथि के रूप में विजय साहू (पूर्व सदस्य, क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन), शुभंकर विश्वास (छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी, हेल्पेज इंडिया रायपुर), गिरवर बंटी साहू (सभापति, नगर पालिक निगम भिलाई) और सुमन सागर सिन्हा (प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद) उपस्थित रहे। अध्यक्षता गजानंद साहू, अध्यक्ष भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ ने की। मुख्य अतिथि सुभाष साव ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहता है। विजय साहू ने कहा कि वे सुख-दुख के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव व ऊर्जा का राज्य सरकार को व्यापक उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर अतिथियों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में भिलाई महासंघ उपाध्यक्ष मंदा वाष्णिकर, बलवीर सिंह सहगल, जे.आर. साहू, बलविंदर सिंह, महेंद्र कुमार सोनवानी, बाबूलाल साहू, जोहनलाल साहू, युवराज साहू, अर्चना मूले, छाया विश्वकर्मा, डॉ. कांतीलाल विश्वकर्मा, मुकेश कुमार, कोहका अध्यक्ष दुलारदास, शिवप्रसाद साहू, ईश्वरी साहू, त्रिवेणी साहू, अनंत राम वर्मा, मानी मानिकपुरी सहित सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।

आशीर्वाद का एक दीया कार्यक्रम को सफल बनाने केबिनेट मंत्री व विधायक गजेन्द्र यादव ने निगम जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने कहा कि जिसने देश का जीवन संवारा, उसको है आशीर्वाद हमारा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 25 वर्षों के अटूट संकल्प और निःस्वार्थ सेवा ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न सेवा कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस एवं सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले ह्यआशीर्वाद का एक दीयाह्न कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में दुर्ग नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदगणों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, तैयारियों एवं विभिन्न जिम्मेदारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की सेवा और समर्पण यात्रा राष्ट्रहित, जनसेवा और गरीब कल्याण के संकल्प की यात्रा रही है। उनके नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निरंतर प्रयास हुआ है। पक्के आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए कार्यों से करोड़ों परिवारों के जीवन में नई आशा और खुशहाली आई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दुर्ग के पुराना पुलिस लाइन मैदान में 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे तक सवा लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मंत्री श्री यादव ने दुर्गवासियों से इस ऐतिहासिक एवं भावपूर्ण आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सवा लाख दीपों का यह प्रकाश प्रधानमंत्री जी की 25 वर्षों की सेवा यात्रा के प्रति जन-जन की कृतज्ञता और शुभकामनाओं का प्रतीक बनेगा।

इसके साथ ही मंत्री श्री यादव ने 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे तक दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से अपने घर, आंगन एवं मोहल्ले में आशीर्वाद का एक दीया जलाने का आह्वान किये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में जलने वाला यह दीपक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति जनता के स्नेह, विश्वास और दीघार्यु की शुभकामनाओं का प्रतीक होगा। मंत्री गजेन्द्र यादव ने नगर निगम के जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी कार्यकताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रधानमंत्री जी की सेवा, समर्पण और राष्ट्रनिर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किये।

किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए शिविरों का आयोजन जारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

धान खरीदी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों एवं उनके सह-हिस्सेदारों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टेक पंजीयन होना अनिवार्य है। इस हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समिति में संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से एग्रीस्टेक पंजीयन का कार्य अपने आश्रित ग्रामों में शिविर आयोजित कर किया जा रहा है।

शिविरों में जिले के सभी तहसील के कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी भी उपस्थित रहकर शासन की महत्वपूर्ण योजना में सहयोग प्रदाय कर रहे है। इस संबंध में पूर्व ही सहकारिता विभाग, अधिकक्षक भू-अभिलेख एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों के संमिति प्रबंधक / प्रभारियो की समीक्षा बैटक जिले के कलेक्टर द्वारा जा चुकि है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना एग्रीस्टेक पंजीयन धान नही बिकेगा, सह खातेदारों का भी पंजीयन होना भी आवश्यक है। उन्होने कहा कि इस वर्ष 2026-27 में धान बिकी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं सह-खातेदारों का बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक हिस्सेदार के नाम से बकेट आईडी बनती है, जिसे एग्रीस्टेक में पंजीयन कराना आवश्यक है। प्रदेश में सर्वाधिक दुर्ग जिले का 458957 बकेट क्लेम (सहमति सत्यापन) का पंजीयन किया जाना है, जिसे शिविर के माध्यम से शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लक्ष्य है। समिति प्रबंधक / प्रभारी एवं संबंधित अमले को सभी लंबित बकेट क्लेम का कार्य समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया था, जिसकी समीक्षा अनुविभागीय अधिकारियों एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा की जा रही है। शिविर के माध्यम से एग्रीस्टेक में बकेट क्लेम के पंजीयन में निरंतर प्रगति हो रही है।

डेलनाज ईरानी ने बताई चुंबक में काम करने की खास वजह

मुंबई अभिनेत्री डेलनाज ईरानी को दर्शक लंबे समय से उनके मजेदार और यादगार किरदारों के लिए जानते हैं। छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों तक, उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिनमें उनकी कॉमेडी और अभिनय का अलग अंदाज देखने को मिला। हालांकि, इस बार डेलनाज कुछ ऐसा लेकर आई हैं जो उनके लिए भी एक तरह की नई चुनौती है। नेटफ्लिक्स की हालिया सीरीज चुंबक में वह एक पारसी किरदार निभा रही हैं। लेकिन इस किरदार को स्वीकार करना उनके लिए इतना आसान नहीं था।

डेलनाज ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने करियर में लंबे समय तक पारसी किरदारों से दूरी बनाए रखी। इसकी वजह पारसी समुदाय को पर्दे पर दिखाने का वह तरीका था, जिसमें अक्सर उनके बोलने के अंदाज, कपड़ों और हाव-भाव को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में जब उन्हें 'चुंबक' का प्रस्ताव मिला तो उन्हें पहली बार लगा कि इस किरदार को बिना किसी बनावटीपन के निभाया जा सकता है। डेलनाज ने कहा, जब भी मनोरंजन जगत में पारसी को दिखाया जाता है तो कई बार उसे जरूरत से ज्यादा मजाकिया और बनावटी अंदाज में पेश किया जाता है। किरदारों को एक खास तरह से बोलते हुए दिखाया जाता है, उनके पहनावे और हावभाव को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जो हमेशा स्वाभाविक नहीं लगता। उन्होंने कहा, सीरीज चुंबक में तारापोरवाला परिवार को काफी सामान्य और सहज तरीके से दिखाया गया है। सीरीज में पांच अलग-अलग परिवारों की कहानी है और तारापोरवाला परिवार को ऐसे पारसी परिवार के रूप में दिखाया गया है, जैसे असल जिंदगी में पारसी बस्तियों में रहने वाले परिवार होते हैं। मुझे यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं लंबे समय तक किसी ऐसे किरदार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, जिसमें किसी कम्युनिटी को केवल हंसी-मजाक या एक खास छवि तक सीमित कर दिया जाए। मेरे लिए जरूरी था कि किरदार में इंसानी पहलू हो और दर्शक उससे जुड़ सकें।

डेलनाज ने कहा, चुंबक का किरदार मेरे लिए खुद को एक अभिनेता के तौर पर चुनौती देने का मौका था। मैंने अपने ही अंदाज में खुद से कहा कि अब आगे बढ़कर यह किरदार करके देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या मैं एक सामान्य पारसी किरदार को सही तरीके से निभा सकती हूं।

'द रिवोल्यूशनरीज' को लेकर भावुक हुईं प्रतिभा रांटा

एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ने बताया कि 'द रिवोल्यूशनरीज' उन प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसमें एक एक्ट्रेस के तौर पर उनसे बहुत कुछ करने की उम्मीद की गई थी। प्रतिभा ने 'प्रतिभा लाहिड़ी' का किरदार निभाने और उससे मिली सीख के बारे में एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी 'द रिवोल्यूशनरीज' के बारे में बिना भावुक हुए बात कर पाऊंगी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने एक एक्टर के तौर पर मुझसे बहुत कुछ मांगा और बदले में मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया। मुझे ऐसे सीन करने को मिले, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, ऐसे सीन जिन्होंने मेरी परीक्षा ली, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे खुद के उन पहलुओं को खोजने में मदद की, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मैं उन्हें किसी किरदार में ला सकती हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'प्रतिभा लाहिड़ी के जरिए मुझे ऐसी महिलाओं को महसूस करने और उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला जो गहराई से प्यार करती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, और फिर भी आगे बढ़ने और मजबूत बने रहने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। महिलाएं जिस तरह से अपनी जिंदगी को संभालकर रखती हैं, उसमें एक शांत मजबूती होती है, और प्रतिभा के जरिए उस पहलू को समझने का मौका मिलने के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी।' प्रतिभा ने इस किरदार के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए डायरेक्टर निखिल आडवाणी का भी शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने आगे कहा, 'निखिल आडवानी, प्रतिभा का किरदार मुझ पर सौंपने और मुझे इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया। जब मैं अपने पहले फिल्मफेयर अवॉर्ड और जिस तरह से सब ने मेरा हौसला बढ़ाया, उसके बारे में सोचती हूं तो मैं अब भी भावुक हो जाती हूं। निखिल सर, आपको मेरे लिए चीयर करते और उस पल को मेरे साथ सेलिब्रेट करते देखना एक ऐसी याद है जिसे मैं हमेशा अपने साथ संजोकर रखूंगी।' इस शो के म्यूजिक के बारे में बात करते हुए प्रतिभा ने बताया कि 'और आएंगे' इस सीरीज के उनके सबसे पसंदीदा गानों में से एक है।

प्रतिभा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'अब भी सब कुछ महसूस कर रही हूं। अब भी थोड़ी भावुक हूं और सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट, इस किरदार, इस टीम और 'द रिवोल्यूशनरीज' को मिले इतने प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूं। हमारा हौसला बढ़ाने और इस सफर को इतना खास बनाने के लिए शुक्रिया।'

ओमः चैप्टर 1 में तस्कर के रोल में नजर आएंगे ममूटी

ममूटी इन दिनों अपनी नई फिल्म 'ओमः चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह धनुष के साथ नजर आने वाले हैं। अब फिल्म से ममूटी के किरदार की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वह बेहद दमदार और रहस्यमयी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ममूटी के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि वह करीब सात साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। उनकी पिछली तमिल फिल्म 'पेरंबु' थी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ममूटी 'बर्मा कार्तिकेयन' नाम के किरदार की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी में वह एक ताकतवर अंतरराष्ट्रीय तस्कर के रूप में दिखाई देंगे।

राखी सावंत के बयान पर भड़कीं कंगना रनौत

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राखी सावंत के हालिया बयान पर ऐसा पलटवार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। राखी ने एक पॉडकास्ट के दौरान कंगना और भाजपा नेता स्मृति ईरानी को लेकर पर्सनल और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद कंगना ने राखी को जवाब देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया। कंगना ने अपने पोस्ट में कहा, ''सिर्फ राखी ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो किसी सफल महिला को देखकर उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी जलन, नाकामी और ईगो को सही ठहराने के लिए सफल महिलाओं पर बार-बार पर्सनल अटैक करते हैं। अब महिलाओं को इस तरह के लगातार होने वाले हमलों से खुद को कमजोर या अपमानित महसूस करना बंद करना चाहिए। हर बार खुद को सही साबित करने के लिए सफाई देते रहना जरूरी नहीं है।'' कंगना ने आगे लिखा, ''राखी ने सफलता के लिए चाहे जितने भी 'फेवर' किए हों, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वह एक स्वीपर की नौकरी तक हासिल नहीं कर पाई। ऐसी नौकरी के लिए भी कुछ क्वालिटी और टैलेंट की जरूरत होती है। फेवर मिले या न मिले, वह कहीं नहीं जाने वाली है, इसलिए बैठ जाओ, मेरी रील्स देखते हुए रोते रहो।''

दरअसल, यह पूरा विवाद राखी सावंत के एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ। राखी ने बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं को लेकर यौन संकेत वाले और आपत्तिजनक कमेंट किए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गए हैं। बातचीत के दौरान राखी कहती हैं, ''मोदी जी इधर-उधर क्यों देख रहे हैं? कंगना में उन्हें हड्डियों के अलावा क्या मिलेगा? मोदी जी, स्मृति, कंगना और इन सभी महिलाओं ने आपको ऐसा क्या दिया कि आपने उन्हें मंत्री बना दिया? तो जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया, वह मैं भी आपको दे सकती हूं।''

रोहित के बयान पर बड़ा विवाद :

टीवी को 'कूड़ेदान' बोलने पर भड़की देवोलीना

अभिनेता रोहित रॉय ने टीवी को 'कूड़ेदान जैसा माध्यम' कहकर चर्चा छेड़ दी है। रोहित ने कहा कि फिल्म स्टार्स में एक खास तरह का स्टाइल और क्लास होता है जो अक्सर टेलीविजन कलाकारों में नहीं दिखता। इस पर अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने रोहित रॉय की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ रोनित रॉय के भाई के तौर पर जानते हैं।

देवोलीना ने रोहित रॉय से पूछा सवाल

रोहित रॉय की बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने कहा कि रोहित उसी माध्यम का अपमान कर रहे थे, जिसने उन्हें काम और पहचान दी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर वह टेलीविजन के बारे में इतना बुरा सोचते थे, तो इतने वर्षों तक इसका हिस्सा क्यों बने रहे।

रोहित रॉय पर भड़की देवोलीना

देवोलीना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'लोगों की एक अजीब आदत होती है कि वे उसी हाथ को काटते हैं जो उन्हें खिलाता है। उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें वह खाते हैं। उनकी बातें बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं। फिल्मों की तो बात छोड़िए, सच कहूं तो मुझे यह भी याद नहीं कि वह किस टीवी सीरीज में थे। सच कहूं तो, ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ रोनित रॉय के भाई के तौर पर जानते हैं। अगर टीवी इतना ही बुरा था, तो उन्होंने इतने वर्षों तक इसका हिस्सा बने रहने का फैसला क्यों किया? अब वह उसी माध्यम को 'डस्टबिन' कह रहे हैं।'

क्या रोहित कर रहे बॉलीवुड स्टार्स पर तंज

देवोलीना ने यह भी कहा कि रोहित की बातों को उन बॉलीवुड एक्टर्स पर तंज के तौर पर देखा जा सकता है जो अक्सर टेलीविजन पर आते हैं। उन्होंने कहा, 'आज हर बड़ा बॉलीवुड स्टार अपनी फिल्मों को प्रमोट करने, रियलिटी शो होस्ट करने और दर्शकों से जुड़े रहने के लिए टेलीविजन पर आता है। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि वे सभी 'डस्टबिन मीडियम' में काम कर रहे हैं? यह बस उसी इंडस्ट्री को नीचा दिखाकर ध्यान खींचने की एक हताश कोशिश लगती है जिसने उन्हें बनाया है।'

क्या बोले थे रोहित रॉय

इससे पहले रोहित रॉय ने किंडल कास्ट से बातचीत में कहा था कि मुझसे यह सवाल कई बार पूछा गया है और कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे एहसान-फरामोश नहीं लगना चाहिए। मगर टेलीविजन एक 'डस्टबिन मीडियम' है। आप इसे आज देखते हैं, यह कल के अखबार जैसा होता है। कल आप इसे भूल जाते हैं। इसलिए भारत में दुर्भाग्य से जिस तरह का और जितना कंटेंट बनाया जा रहा है, उसमें शायद ही कोई क्रिएटिविटी होती है।'

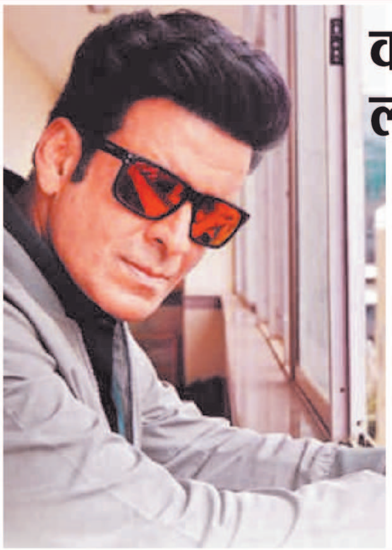

कभी-कभी मेरे अंदर का गांव का जो लठैत है, वो अंदर से बाहर आना चाहता है

कद्दावर अभिनेता मनोज बाजपेयी करीब तीन दशकों से अपनी भूमिकाओं के साथ -नित नए प्रयोग करते जा रहे हैं। मनोरंजन के नए डायनामिक्स के साथ भी उन्होंने कदमताल करना सीखा, यही वजह है कि सिनेमा के साथ -साथ वे ओटीटी का भी बड़ा चेहरा बन गए। इन दिनों वे चर्चा में हैं अपनी नई फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' को लेकर।

तीस सालों से भी ज्यादा का सफर तय कर चुके मनोज बाजपेयी सोशल मीडिया पर अच्छे-खासे एक्टिव हैं, मगर वे यहां होने वाली उठापटक से कितना प्रभावित होते हैं? उनके लिए लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज कितना मायने रखते हैं? इस पर वे कहते हैं, 'मैं लाइक्स और कमेंट्स नहीं देखता। अब इतने साल बाद मुझे ये देखना पड़े तो लानत है मेरे काम, मेरी तीस साल की जर्नी पर'।

जिस स्थिति से गुजरा मैं ही जानता हूं

उन जैसे सोबर अभिनेता को क्या कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? इस पर वे तपाक से कहते हैं, 'बिलकुल, हाल-फिलहाल कुछ ही महीने पहले जब मेरी एक फिल्म के टाइटल (घूसघोर पंडित) को लेकर विवाद हुआ, उस पर जो धमकियां और जान की धमकी मिली और मैं जिस स्थिति से गुजरा मैं ही जानता हूं। क्योंकि उस फिल्म का चेहरा मैं हूं, तो मुझे ये सब सहना पड़ा। खैर अब तो फिल्म का शीर्षक बदल दिया गया है। अब क्या है न कि आप कोई भी फिल्म बना रहे हो, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो उसके विरोध के स्वर कहीं से भी आ सकते हैं। आज के दौर में ट्रोलिंग बहुत आसान है। कोई भी कहीं से कुछ भी बोल सकता है। अगर आपको गाली देना हो तो बड़े से बड़े लोग भी अछूते नहीं हैं।'

कभी-कभी मेरे अंदर का लठैत जाग उठता है

ट्रोलिंग को हैंडल करने के मसले पर वे कहते हैं, 'या तो आप उसको गंभीरता से लीजिए या ये समझिए कि कुछ लोग हैं, जो आपको अपने स्तर पर लाना चाहते हैं, ताकि आप ऐसे जवाब दें, रिएक्ट करें। जाहिर है आप उनके स्तर पर नहीं जाना चाहेंगे। आप अपने जीवन में कितने ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं? जो लोग जहीन लोग हैं, जो पढ़ते-लिखते हैं, जो अच्छा देखते हैं, जिनके साथ ज्ञान मिलता है, हम उनके साथ उठते-बैठते हैं। बाकी समय परिवार को जाता है, तो मैं कभी जवाब नहीं देता। मगर कभी-कभी मेरे अंदर का गांव का जो लठैत है, वो अंदर से बाहर आना चाहता है। फिर मैं कहता हूं, मनोज यार, किस-किस के मुंह लगोगे? जो आदमी अभी उठा होगा, जो अपने पिताजी से पैसे मांगने वाला होगा कि आज जरा फिल्म देखने जाना है या मुझे आइसक्रीम खानी है या अपने पिताजी को बेवकूफ बनाना चाह रहा होगा कि कैसे भी पैसे हड़प कर लूं। वो आपको गाली दे रहा है। एक आदमी जो 18 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया, आप अब उसको गाली दे रहे हो, इतना काम करने के बाद। अगर उसको इतनी भी शर्म नहीं, तो क्या ही कहें? मुझे तो छोड़िए, ये बड़े से बड़े लोगों को गाली देते हैं। ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना?'

हर बार विरासत हार रही है

उनकी हालिया फिल्म में 'विरासत वर्सेज डेवलपमेंट' की लड़ाई दिखाई गई है। इस मुद्दे पर वे कहते हैं, 'विकास बनाम विरासत, विकास बनाम यादें, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और हर बार जो है, विरासत हार रही है। धरती बदल रही है और आधुनिकता के नाम पर जिस तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसमें हम अपनी मिट्टी और विरासत की पहचान कायम नहीं रख पा रहे हैं। सीधी-सी बात है, हमारे एयरपोर्ट्स और स्टेशन हमारी 700, 600 या 1000 साल पुरानी वास्तुकला से प्रेरणा लेकर क्यों नहीं बन सकते? क्यों हमेशा वो मैनहैटन या न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट ही लगें? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। हर जगह की अपनी पहचान है। अमेरिका की अपनी और हिंदुस्तान की अपनी। राजस्थान में कुछ बन रहा है तो उसमें राजस्थान क्यों नहीं दिखना चाहिए? विकास बनाम विरासत की ये लड़ाई बहुत पुरानी है और इस फिल्म में भी यही संघर्ष है। एक तरफ मास्टर जी हैं, जो अपनी यादों और विरासत को बचाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनकी जरूरतें बढ़ गई हैं और उनके लिए विकास जरूरी है। ये कहानी 50 साल पुरानी नहीं, आज हमारे आस-पास चल रही लड़ाई है।'

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छुई में की पंचायत और मिडिल स्कूल भवन निर्माण की घोषणा

मेरी बेटी, मेरा अभिमान के तहत सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए जरूरी सुविधाएं की जाएंगी सुनिश्चित, मंत्री ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम छुई में ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी मांगों और समस्याओं को आत्मीयता से सुना तथा गांव में सुविधाओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि गांव के विकास की सही दिशा ग्रामीणों की जरूरतों और सुझावों से ही तय होती है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। ग्रामीणों से संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम छुई में नवीन पंचायत भवन और मिडिल स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विकास का सीधा लाभ ग्रामीणों के जीवन में दिखाई दे। उन्होंने कहा कि बच्चे ही प्रदेश और देश का भविष्य हैं, इसलिए उनकी बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्षेत्र के 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास तैयार किए गए हैं तथा 35 और स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाएंगे। दो-तरफा संवाद की सुविधा से एक स्थान से कई स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से विषय विशेषज्ञों की कक्षाओं के साथ विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और करियर के लिए मार्गदर्शन भी मिलेगा। आने वाले समय में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विज्ञान और गणित जैसे विषयों को सरल एवं रुचिकर तरीके से समझाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, मेरा अभिमान के तहत सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जिन स्कूलों में बालिका शौचालय नहीं हैं, वहां शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। इसी तरह जिन गांवों में मुक्तिधाम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मुक्तिधाम शेड निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी, ताकि ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकें। इसके लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

उप मुख्यमंत्री ने पीएम आवास हितग्राहियों से घर पहुंच की मुलाकात

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम छूही में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित श्रीमती रंभा हठीले और होमित हठीले के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने हितग्राहियों से आवास निर्माण, योजना से मिले लाभ और आवास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

आज शाम घर-घर जलाएं आशीर्वाद का दिया

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीणों से 17 सितंबर शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ह्यआशीर्वाद का दियाह्न में सहभागिता करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर प्रत्येक घर के बाहर दीप जलाकर उन्हें शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि यह अवसर देश के विकास और सेवा के संकल्प को मजबूत करने का भी अवसर है। उन्होंने ग्रामीणों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की।

खास खबर

सेवा संकल्प अभियान : जिले में प्रज्ज्वलित होंगे 1 लाख 8 हजार दीप

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

तीनों ब्लॉक मुख्यालयों में शाम 5 बजे से आयोजन शाम 7 बजे होगा सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर आज आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के तहत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 1 लाख 8 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा को समर्पित रहेगा।

मोहला के मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य आयोजन होगा, जिसमें 500 से अधिक नागरिक शामिल होंगे और 5 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रदर्शन सहित विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार जिले के तीनों ब्लॉक मुख्यालयों में शाम 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तथा शाम 7 बजे सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। मोहला में मिनी स्टेडियम, मानपुर में इंद्रप्रस्थ स्टेडियम तथा अंबागढ़ चौकी में शिवनाथ नदी घाट पर विशेष आयोजन किए जाएंगे।

कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में नागरिकों को दीप वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह ने जिला मुख्यालय मोहला के जय स्तंभ चौक एवं फव्वारा चौक में नागरिकों को दीप वितरित किए। उन्होंने नागरिकों से आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने तथा 17 सितंबर को शाम 7 बजे अपने घर, दुकान एवं प्रतिष्ठान में दीप प्रज्ज्वलित करने की अपील की। जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में सहभागी बनकर सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ को जनभागीदारी के उत्सव के रूप में मनाएं।

सेवा संकल्प अभियान - महतारी वंदन योजना की राशि से तन्मय के पोषण को मिला सहारा

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने श्रीमती हेमा साहू की अपने दो वर्षीय बेटे तन्मय के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य को लेकर चिंता को कम किया है। छुरिया विकासखंड के ग्राम बागद्वार की श्रीमती हेमा साहू के लिए महतारी वंदन योजना आर्थिक सहायता के साथ अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण का सहारा बनी है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग वह अपने दो वर्षीय बेटे तन्मय के पोषण और स्वास्थ्य पर कर रही हैं। श्रीमती हेमा साहू ने बताया कि जन्म के समय तन्मय का वजन 2 किलोग्राम था। बेटे के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए वह महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री खरीद रही हैं। घर में उपयोग होने वाले सामान्य खाद्य पदार्थों के साथ अब तन्मय के भोजन में पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि बेटे तन्मय को दोनों समय के भोजन में मिश्रित दाल सहित पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर उसके स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में तन्मय का वजन 8 किलो 700 ग्राम हो गया है। पहले की तुलना में बेटे तन्मय के वजन और स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। श्रीमती हेमा साहू ने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस राशि का उपयोग वह अपने बेटे के अच्छे पोषण के लिए कर पा रही हैं।

कवर्धा मेडिकल कॉलेज के पहले बैच ने डिप्टी सीएम शर्मा ने किया संवाद

विद्यार्थियों ने भी संवाद के दौरान अपनी बात रखी और कॉलेज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले के मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को ऐतिहासिक प्रथम बैच के प्रथम दिवस के अवसर पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके अनुभव, अपेक्षाओं तथा चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में कबीरधाम कलेक्टर तुलिका प्रजापति, मेडिकल कॉलेज की डीन सहित कॉलेज का अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्टाफ मौजूद रहा।

मेडिकल कॉलेज में प्रथम बैच के विद्यार्थियों के आगमन को संस्थान के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इसी अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से सीधे बातचीत करते हुए उनके विचार जाने। उन्होंने विद्यार्थियों से मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के अनुभव, उपलब्ध सुविधाओं तथा शिक्षा के दौरान उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी संवाद के दौरान अपनी बात रखी और कॉलेज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के वातावरण में विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया। प्रथम बैच के विद्यार्थियों के लिए यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा कि उन्हें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिला। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में भी चर्चा हुई।

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने भी कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े विषयों की जानकारी ली। मेडिकल कॉलेज की डीन तथा अन्य स्टाफ ने कार्यक्रम के आयोजन और विद्यार्थियों से संबंधित व्यवस्थाओं में सहभागिता निभाई।

कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच की शुरूआत जिले में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलने के साथ ही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी नई संभावनाएं बनी हैं। प्रथम बैच के विद्यार्थियों के लिए आयोजित यह संवाद कार्यक्रम कॉलेज के शैक्षणिक सफर की शुरूआत के साथ यादगार अवसर बना। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और उपमुख्यमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए।

नगर निगम में मनाया गया अभियंता दिवस, भारतरत्न विश्वेश्वरैया को किया याद

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

अभियंता दिवस के अवसर पर मंगलवार को नगर निगम के कार्यपालन अभियंता कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम आयुक्त जी.आर. मरकाम की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों एवं इंजीनियरों ने महान दूरदर्शी और भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और एक-दूसरे को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

आधुनिक भारत के निर्माण में रहा अभूतपूर्व योगदान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुक्त जी.आर. मरकाम ने एम. विश्वेश्वरैया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने आधुनिक भारत में बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में मील का पत्थर साबित होने वाली भूमिका निभाई। मैसूर सरकार के साथ मिलकर उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों व कारखानों की नींव रखी। राष्ट्र निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1955 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न से नवाजा था।

आयुक्त ने निगम के इंजीनियरों से उनके पदचिन्हों पर चलने और निष्ठापूर्वक कार्य करने की अपील की। कार्यपालन अभियंता दीपक खांडे और यू.के. रामटेके ने भी विचार व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

आयोजन के दौरान प्रभारी कार्यपालन अभियंता प्रणय मेश्राम, प्रभारी सहायक अभियंता सुश्री सुषमा साहू, उपअभियंता पिंकी खाती, अनूप पांडे, तिलकराज ध्रुव सहित तकनीकी शाखा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सड़क विकास को मिली बड़ी सौगात, 370.40 करोड़ के कार्य स्वीकृत

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मजबूत हो रहा जिले का सड़क नेटवर्क, 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले को सड़क विकास की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले में 6 प्रमुख सड़क कार्यों के लिए कुल 370.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यों में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के साथ पुल-पुलिया निर्माण भी शामिल है। इनके पूरा होने से जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा बेहतर सड़क संपर्क से विकास गतिविधियों को गति मिलेगी।

इनमें सबसे बड़ा कार्य राजनांदगांव-डोंगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर राज्य मार्ग क्रमांक-24 का है। किमी 2/8 से 100/2 तक 93.90 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 282.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण मार्ग के बेहतर होने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इसी तरह मानपुर से बसेली-मदनवाड़ा-कारेकट्टा-सीतागांव मार्ग के 30.65 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए आकस्मिकता निधि अंतर्गत 42.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कौड़ीकसा-अरजकुण्ड-पाटन मार्ग के किमी 8 से 25/8 तक 17.80 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं पुल-पुलिया निर्माण सहित कार्य के लिए 30.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा कुदुरघोड़ा से वाड़वी मार्ग के 6 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए 5.90 करोड़ रुपये, कहड़बरी-लोहत्तर मार्ग के 6.60 किलोमीटर हिस्से को 14 मीटर चौड़ाई में मजबूतीकरण के लिए 4.42 करोड़ रुपये तथा रेतेगांव से हुरेली मार्ग के 4 किलोमीटर निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित के लिए 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आवागमन के साथ कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से जिले के गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। इससे आम नागरिकों के आवागमन के साथ कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क सुविधा से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। जिले में स्वीकृत ये सड़क कार्य क्षेत्र के समग्र विकास और मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

सौगात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से बदली ग्राम रानी तराई की धूलेश्वरी बाई की जिंदगी

पक्के घर से मिली खुशियों की सौगात, धूलेश्वरी बाई का परिवार अब चिंता मुक्त

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवाकाल में गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का संकल्प निरंतर साकार हो रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम रानीतराई निवासी दुलेश्वरी बाई को पक्का आवास मिलने से उनके परिवार का जीवन आसान हो गया है। कभी कच्चे मकान में बारिश और कीड़े-मकोड़ों की समस्या से परेशान रहने वाला परिवार अब पक्के घर में सुख-शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है।

दुलेश्वरी बाई ने बताया कि पहले उनका घर कच्चा था। बारिश के दिनों में घर में पानी आने से बच्चों की पुस्तकें और अन्य सामान गीले हो जाते थे। कीड़े-मकोड़ों से भी परेशानी होती थी। परिवार को हर मौसम में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 1 लाख 20 हजार रूपए की सहायता से उनका पक्का मकान बन सका है। उन्होंने कहा कि पक्का घर बनने के बाद अब परिवार को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से राहत मिली है। बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं और पूरा परिवार बिना किसी चिंता के सुख-शांति से रह रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना से उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है।

महतारी वंदन योजना से लोकेश्वरी के जीवन में आया आत्मनिर्भरता का उजास

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सामने लाया जा रहा है। इसी कड़ी में महतारी वंदन योजना डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अमलीडीह की लोकेश्वरी साहू के लिए आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनी है। लोकेश्वरी साहू बताती हैं कि योजना से जुड ? से पहले उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। घर-परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। महतारी वंदन योजना की शुरूआत से ही वे इससे जुड़ी हुई हैं और योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वे बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे अपनी गर्भावस्था के दौरान देखभाल तथा बच्चों के स्वास्थ्य, खान-पान और पोषण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इसके साथ ही घर की छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए अब उन्हें पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता ने उन्हें अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने का आत्मविश्वास दिया है। लोकेश्वरी साहू कहती हैं कि महतारी वंदन योजना उनके लिए केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार बनी है। आज वे पहले की अपेक्षा स्वयं को अधिक आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करती हैं। लोकेश्वरी साहू ने महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए ऐसी जनहितकारी योजनाएं निरंतर संचालित होती रहनी चाहिए।

ग्राम पलान्दुर, पंडरापानी, गहिराभेड़ी, बरगांव, कोपेडीह व चिखली वार्ड में मोबाईल कैम्प का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एसओपी अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। मोबाईल कैम्प के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा पात्र आवेदक को योजनाओं से लाभान्वित करने आवेदन प्राप्त किए जा रहे है।

इसी क्रम में डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पलान्दुर, छुरिया विकासखंड के ग्राम पंडरापानी एवं गहिराभेड़ी, डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बरगांव, राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कोपेडीह एवं नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 5 चिखली में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया गया। मोबाईल कैम्पों में लगभग 338 श्रमिक उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत 88 श्रमिकों ने पंजीयन हेतु आवेदन किया गया।

शिविर में 23 वैधता अवधि समाप्त होने वाले श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण आवेदन किया गया। 8 हितग्राहियों के संशोधन एवं 4 हितग्राहियों का योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शिविर में ई-श्रम साथी एप के माध्यम से 5 रजिस्ट्रेशन एवं 94 श्रमिकों का ई-केवायसी सत्यापन किया गया। शिविर में 148 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई एवं ब्रोसर का वितरण किया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चलाया जाएगा, आज से 2 अक्टूबर तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

रेलवे बोर्ड के निदेर्शानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में स्वच्छता ही सेवा–2026 अभियान का आयोजन 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत की थीम पर किया जा रहा है। इसके पश्चात स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा। इस अवधि के दौरान विभिन्न स्वच्छता, जनजागरूकता एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाने के साथ–साथ स्वच्छता को जन–आंदोलन का रूप देना, नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, कचरे के उचित प्रबंधन एवं पृथक्करण को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ रेलवे परिवेश तैयार करना है।

अभियान के दौरान दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2026 को रेलवे स्कूलों एवं कॉलोनियों में विद्यार्थियों एवं युवाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा पृथक्करण, जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए रेलवे की स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का भ्रमण, संवाद, वाद–विवाद, चित्रकारी प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 एवं 20 सितम्बर 2026 को कचरा संवेदनशील स्थलों एवं क्लीन्लिनेस टारगेट यूनिट्स (सीटीयूस) की विशेष सफाई कर उनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

21 एवं 22 सितम्बर 2026 को स्वच्छ स्टेशन–स्वच्छ रेलगाड़ी एवं स्वच्छ सार्वजनिक स्थान अभियान के अंतर्गत स्टेशनों एवं चयनित ट्रेनों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ट्रेनों में शौचालय, कोच की स्वच्छता, लिनेन तथा ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग (ओबीएचएस) एवं पैन्ट्रीकार की स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा। स्टेशनों पर सूखे एवं गीले कचरे के लिए अलग–अलग डस्टबिन तथा प्लास्टिक मुक्त प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

23 एवं 24 सितम्बर 2026 को जनभागीदारी के तहत रेलवे कॉलोनियों में घर–घर जागरूकता अभियान, होम कोंपोस्टिंग एवं बायो–कोंपोस्ट के प्रति जागरूकता, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम होंगे। साथ ही जीरो–वेस्ट खेल प्रतियोगिताएं तथा नेकी की दीवार एवं आरआरआर संग्रह केंद्रों के माध्यम से पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिनाँक 25 एवं 26 सितम्बर 2026 को जीरो–वेस्ट थीम पर स्काउट गाइड एवं स्कूली बच्चों द्वारा खेल के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। 27 सितम्बर को विरासत एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान, थीम आधारित ब्रांडिंग तथा यात्रियों को जिम्मेदार पर्यटन एवं नागरिक व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। 28 एवं 29 सितम्बर 2026 को स्वच्छता से समृद्धि की अवधारणा के तहत कबाड़ से कला एवं अनुपयोगी रेलवे सामग्री से उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

30 सितम्बर 2026 को सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर आयोजित कर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच, पीपीई किट एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण तथा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने वाले सफाई मित्रों एवं स्वच्छाग्रहियों का सम्मान भी किया जाएगा। अभियान के दौरान 01 अक्टूबर 2026 को एक दिन, एक घंटा, एक साथ श्रमदान कार्यक्रम में रेलकर्मियों, उनके परिवारों एवं आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 02 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर विभिन्न स्वच्छता एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई : नक्सलियों का जखीरा बरामद, आठ किलो जिलेटिन समेत कारतूस जब्त

बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद

बरामद सामग्री में 315 बोर का एक देशी कट्टा, 315 बोर के 49 जिंदा राउंड, 303 रायफल के 25 जिंदा राउंड और 12 बोर के 34 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा 303 रायफल का बट प्लेट, बोल्ट, खाली मैगजीन एवं अन्य पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से करीब 8 किलोग्राम जिलेटिन, छह वाकी–टॉकी सेट मय चार्जर, एक मेन पेक सेट, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं कॉपर वायर, डेटोनेटर वायर, क्लच वायर, बैटरी, सेल, स्विच, सॉकेट, अन्य विस्फोटक सामग्री और टूल्स भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद हथियार एवं विस्फोटक सामग्री को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त कर लिया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नई दृष्टिबिंदु / बीजापुर

बीजापुर के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। बड़ेआलवाड़ा के जंगल–पहाड़ी क्षेत्र में हुई सर्चिंग के दौरान 315 बोर का देशी कट्टा, 49 जिंदा राउंड, 303 रायफल के 25 राउंड, 12 बोर के 34 कारतूस और करीब 8 किलो जिलेटिन मिला। ग्राम बड़ेआलवाड़ा के समीप जंगल–पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक एवं अन्य सामग्री बरामद की गई।

संयुक्त टीम ने चलाया था सर्चिंग अभियान

पुलिस के मुताबिक 15 सितंबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में थाना फरसेगढ़, डीआरजी बीजापुर और बीडीएस की संयुक्त टीम ने बड़ेआलवाड़ा के पास जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान संदिग्ध रूप से छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद हुई। बीडीएस टीम ने आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया और डिमाइनिंग के बाद सामग्री को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया।

आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जनकराम ध्रुव का राजनांदगांव आगमन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं नवागढ़ विधायक सम्माननीय जनकराम ध्रुव जी का राजनांदगांव आगमन हुआ। सर्किट हाउस में ध्रुव जी का फूल–माला और आदिवासी गमछा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।

इस अवसर पर आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष लादूराम तुमरें जी, उपाध्यक्ष उमर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष ललित कुमरे जी, पार्षद रीसी शास्त्री जी, सरपंच लाला नेताम, ओकेश कुमार, महेश्वर साहू जी, अशोक चंद्रवंशी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पत्रकार का लहजा नरम और सवाल सख्त होना चाहिए : अब्दुल वदूद साजिद

नई दृष्टिबिंदु / भोपाल

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में बुधवार को एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक 'इंकलाब' (उर्दू दैनिक) के संपादक अब्दुल वदूद साजिद ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए अपने पत्रकारिता के चार दशक के अनुभव साझा किए। कर्नल गद्दाफी एवं सद्दाम हुसैन जैसे वैश्विक नेताओं से किए गए साक्षात्कार की चर्चा करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि असली पत्रकार वही है जो बिना किसी पूर्वग्रह या बिना तैयारी के भी परिस्थितियों को संभालने का हुनर रखता है। पत्रकार हर घटना से लगातार सीखता रहता है।

उन्होंने छात्रों को हमेशा सकारात्मक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय का पहिया घूमता रहता है, अच्छा और बुरा दौर आता–जाता रहता है। मुख्यधारा की मीडिया में किसी स्थिति से लोग खुश या नाराज हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार को किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप अकेले हों तो आईने के सामने खड़े होकर यह दोहराएं कि 'मुझे सब कुछ आता है' ताकि आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन जब आप किसी दूसरे से बात कर रहे हों, तब आपका व्यवहार और भाव हमेशा सीखने वाला होना चाहिए।

इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के लहजे और गरिमा पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक पत्रकार वार्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछते नहीं, बल्कि 'दागते' हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सवाल पूछने और दागने में बहुत फर्क होता है। हमारे सवाल सख्त और तीखे हो सकते हैं, लेकिन हमारा लहजा हमेशा नरम और शालीन होना चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब बहस या लड़ाई करना नहीं होता।

स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि भारत के आजादी के आंदोलन में उर्दू पत्रकारिता ने एक बागी पत्रकारिता की भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रो. संजय द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक डॉ. लाल बहादुर ओझा, एडजंक्ट प्रोफेसर गिरीश उपाध्याय, डा. गरिमा पटेल, डा.शलभ श्रीवास्तव, डा.बबिता रानी घोष, डा.उदित्य सिंह सेंगर सहित छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थी विनम्र तिवारी ने श्री साजिद का विभाग की ओर से पुस्तकें भेंट कर स्वागत किया।

अवलोकन

श्री साजिद ने विश्वविद्यालय में लगी समाचार पत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण लेकर व्यवसाय का सुनहरा मौका, महापौर ने की ऑनलाइन आवेदन करने की अपील

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है। नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। महापौर मधुसूदन यादव ने ऋण लेकर स्वावलंबी बनने की अपील की है।

योजना के तहत बैंकों से तीन चरणों में ऋण दिया जाता है – पहला ऋण 15 हजार रुपये, अदायगी पर दूसरा ऋण 25 हजार और दूसरे की अदायगी पर तीसरा ऋण 50 हजार रुपये। नियमित अदायगी पर बैंक ब्याज में 7 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

निगम आयुक्त जी.आर. मरकाम ने बताया कि अब तक कुल 2920 पथ विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को ऋण दिया जा चुका है। इसमें 2157 लोगों को प्रथम ऋण 15 हजार, 618 को द्वितीय ऋण 25 हजार और 145 को तृतीय ऋण 50 हजार दिया गया है। अब तक 4.54 करोड़ का ऋण और 9 लाख रुपये ब्याज अनुदान दिया जा चुका है। लंबित प्रकरणों में बैंकों को स्वीकृति और वितरण के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर यादव ने बताया कि फेरी और छोटा व्यवसाय करने वाले गरीब वर्ग को आर्थिक संबल देना योजना का उद्देश्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड (मोबाइल लिंक), बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र, 2 फोटो और मोबाइल लाना अनिवार्य है। नजदीकी चॉइस सेंटर या कंप्यूटर दुकान से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग बढ़ी बदमाशों की हिम्मत

रायपुर। जिले के खरोरा इलाके में रेस्टहाउस के सामने किराना दुकान के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र और सोने का हार झपट लिया। वारदात के बाद आरोपी बाइक से तेज रफ्तार में फरार हो गए। फिलहाल खरोरा थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार खरोरा निवासी साहू परिवार मूल रूप से इल्दा गांव का रहने वाला है। 16 सितंबर को निजी काम से बाजार आया था। काम पूरा करने के बाद सभी वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रेस्टहाउस के सामने किराना दुकान के पास ब्रेकर के आसपास बाइक सवार बदमाशों ने महिला को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश महिला के करीब पहुंचे और अचानक उसके गले से मंगलसूत्र और सोने का हार झपट लिया।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100